नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 08
दि. 08.10.2025,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

कफ सिरप का ज़हर: 23 मासूमों की मौत से दहला देश, सुप्रीम कोर्ट में CBI जांच की मांग

नई दिल्ली। भारत एक बार फिर दवा उद्योग की लापरवाही से हिल गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीला कफ सिरप पीने से अब तक 23 मासूम बच्चों की जान जा चुकी है। इन मौतों ने न सिर्फ प्रशासन को झकझोर दिया है, बल्कि आम जनता के बीच दवाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहरीले रसायनों से बनी यह दवा, जो बच्चों के खांसी-जुकाम के इलाज के नाम पर दी गई थी, अब मौत की बोतल बन चुकी है। मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और पंजाब सरकारों ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें एडवोकेट विशाल तिवारी ने इस पूरे प्रकरण की CBI जांच कराने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि दवा उद्योग में लगातार हो रहे ऐसे हादसों से यह स्पष्ट है कि देश में दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी की कोई ठोस प्रणाली नहीं है। इसलिए अदालत से आग्रह किया गया है कि वह केंद्र सरकार को निर्देश दे कि एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति गठित की जाए, जो देशभर में दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करे।

इस घटना की शुरुआत मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से हुई, जहाँ 2 सितंबर से बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। स्थानीय अस्पतालों में दर्जनों बच्चे भर्ती किए गए, जिनमें से 19 ने दम तोड़ दिया।

यही हाल राजस्थान के दौसा जिले में भी हुआ, जहाँ 4 बच्चों की मौत हुई। जांच में पाया गया कि सभी ने एक ही कफ सिरप — "कोल्ड्रिफ" — का सेवन किया था।

सिरप बनाने वाली कंपनी पर शिकंजा

इस घोटाले की जड़ तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स तक पहुंची, जो कोल्ड्रिफ सिरप बनाती है। राज्य के ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पाँच दिन के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि कंपनी की फैक्ट्री में दवा उत्पादन से जुड़ी 350 से अधिक गंभीर गड़बड़ियाँ मिली हैं — जिनमें कई को "क्रिटिकल" और "मेजर" श्रेणी में रखा गया है।

जांच रिपोर्ट में सामने आई भयावह सच्चाइयाँ

तमिलनाडु की जांच टीम द्वारा की गई पड़ताल में जो तथ्य सामने आए, वे चौंकाने वाले हैं।

फैक्ट्री के अंदर गंदगी फैली थी, उत्पादन कक्ष में कोई उचित वेंटिलेशन नहीं था, कई मशीनें टूटी और जंग लगी हुई थीं। वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को दवा निर्माण का कोई वैज्ञानिक प्रशिक्षण नहीं था।

सबसे भयावह खुलासा यह हुआ कि दवा बनाने में इस्तेमाल हुआ प्रोपीलीन ग्लाइकोल फार्मा-ग्रेड का न होकर औद्योगिक गुणवत्ता का था, जो डायथिलीन ग्लाइकोल (DEG) और एथिलीन ग्लाइकोल (EG) जैसे घातक रसायनों से दूषित था।

इन्हीं रसायनों के कारण बच्चों की किडनी फेल हो गई और उनकी मौत हो गई।

जांच में यह भी पाया गया कि कंपनी ने 50 किलो प्रोपीलीन ग्लाइकोल बिना किसी बिल के खरीदा था, और दवा को प्लास्टिक पाइपों से ट्रांसफर किया जा रहा था। यह प्रक्रिया न केवल गैरकानूनी थी, बल्कि दवा को सीधे प्रदूषित करने वाली थी। दवा छानने की कोई व्यवस्था नहीं थी और फैक्ट्री का गंदा केमिकल युक्त पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे नालियों में छोड़ा जा रहा था।

गुजरात की कंपनियों में भी मिला ज़हर

मध्य प्रदेश सरकार ने एहतियात के तौर पर 19 दवाओं के सैंपल लिए, जिनमें से गुजरात की दो कंपनियों — रीलाइफ सिरप और रेस्पिफ्रेस टीआर सिरप — के नमूनों में भी DEG और EG की अत्यधिक मात्रा पाई गई। परिणामस्वरूप इन दोनों सिरपों की बिक्री और स्टॉक पर तुरंत रोक लगा दी गई है, जबकि गुजरात सरकार को विस्तृत जांच के लिए पत्र लिखा गया है।

48% जहर मिला कोल्ड्रिफ सिरप में

चेन्नई की सरकारी ड्रग्स टेस्टिंग लैब में भेजे गए सैंपलों की रिपोर्ट ने इस भयावह सच्चाई को उजागर कर दिया कि कोल्ड्रिफ सिरप (बैच नंबर SR-13) में 48.6% वॉल्यूम तक डायथिलीन ग्लाइकोल पाया गया, जो इसे "Not of Standard Quality" घोषित करने के लिए पर्याप्त था। इस मात्रा का अर्थ है कि सिरप का लगभग आधा हिस्सा जहरीले रसायन से बना था। बाकी चार दवाओं (रेस्पोलाइट D, GL, ST और हेप्सैंडिन सिरप) को फिलहाल मानक गुणवत्ता का बताया गया है।

बच्चों की मौत और उद्योग की निष्ठुरता

इन मौतों ने उस दर्दनाक सच्चाई को उजागर किया है कि भारत के कई छोटे दवा निर्माता निगरानी और नियमन की कमी का फायदा उठा रहे हैं। सस्ती दवाओं के नाम पर बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। हर बार की तरह प्रशासनिक जांचें शुरू होती हैं, रिपोर्टें आती हैं, और फिर धीरे-धीरे मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन इस बार स्थिति इतनी गंभीर है कि देशभर में आक्रोश फैल गया है।

सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद की निगाहें

अब पूरा देश सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहा है। एडवोकेट विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए न केवल CBI जांच जरूरी है, बल्कि यह भी अनिवार्य है कि एक राष्ट्रीय स्तरीय औषधि सुरक्षा आयोग बने जो प्रत्येक दवा निर्माता की नियमित ऑडिटिंग करे और किसी भी उल्लंघन पर तुरंत लाइसेंस रद्द करने की शक्ति रखे।

इन मासूमों की मौत ने भारत को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है — क्या विकास की इस दौड़ में हमने मानवीय संवेदना को पीछे छोड़ दिया है? क्या हमारे सिस्टम की खामियों की कीमत अब बच्चों की जान होगी?

यह सिर्फ एक सिरप का मामला नहीं, यह देश की चिकित्सा व्यवस्था पर लगा वह दाग है जो तब तक नहीं मिटेगा, जब तक हर जिम्मेदार संस्था यह सुनिश्चित न कर दे कि दवा अब इलाज का नाम हो, मौत का नहीं।

महाराष्ट्र को नई दिशा देने की तैयारी — झोपड़पट्टी पुनर्विकास, रत्न नीति और जल प्रबंधन पर सरकार के ऐतिहासिक फैसले

मुंबई। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को कई ऐसे निर्णय लिए गए जो राज्य की सूरत और विकास की दिशा को गहराई से प्रभावित करने वाले साबित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 9 बड़े फैसले लिए गए, जिनमें झोपड़पट्टी समूह पुनर्विकास योजना, अपशिष्ट जल उपचार नीति और रत्न-आभूषण उद्योग को बढ़ावा देने वाली नई नीति प्रमुख हैं। राज्य सरकार का दावा है कि ये फैसले न केवल शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण को गति देंगे, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार और बेहतर जीवन सुविधा भी प्रदान करेंगे।

महाराष्ट्र के शहरी परिदृश्य में सबसे अहम फैसला झोपड़पट्टी समूह पुनर्विकास योजना को लेकर लिया गया। मुंबई और अन्य शहरों में बड़ी संख्या में मौजूद झोपड़ियों को आधुनिक आवासीय परिसरों में बदलने के लिए बृहन्मुंबई झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। इस योजना के तहत कम से कम 50 एकड़ के क्षेत्र को चिन्हित किया जाएगा, जिसमें 51% से अधिक झोपड़पट्टी का हिस्सा होना अनिवार्य होगा। पुनर्विकास परियोजनाओं को सरकारी संस्थानों के साथ संयुक्त उपक्रम या निजी बिल्डरों के माध्यम से टेंडर प्रक्रिया द्वारा संचालित किया जा सकेगा। गृहनिर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति इन परियोजनाओं को अंतिम स्वीकृति देगी। इस योजना में तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) जोन-1 और 2 में आने वाली झोपड़पट्टियों को भी शामिल किया जा सकेगा।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि केंद्र सरकार अपने अधिकार क्षेत्र की जमीनों को इस योजना में शामिल करने की अनुमति देती है, तो उन क्षेत्रों को भी

पुनर्विकास के दायरे में लाया जाएगा। निजी भूमि मालिक भी इस योजना में भाग ले सकेंगे। इससे न केवल झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लाखों लोगों को पक्का मकान मिलेगा, बल्कि शहरी क्षेत्रों का पर्यावरण और जीवनस्तर भी सुधरेगा।

इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के रत्न और आभूषण क्षेत्र को नई उड़ान देने के लिए "महाराष्ट्र राज्य रत्न और आभूषण नीति–2025" की घोषणा की है। इस नीति के तहत सोने, चांदी, हीरे और रत्न उद्योगों में 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश और 5 लाख से अधिक नए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। मुंबई, नाशिक, पुणे और नागपुर जैसे शहरों को रत्न उद्योग के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे महाराष्ट्र को वैश्विक स्तर पर आभूषण निर्माण का हब बनाया जा सके।

शहरी पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर भी कैबिनेट ने एक दूरगामी निर्णय लिया। राज्य के 424 शहरों और नगर परिषदों में अपशिष्ट जल उपचार और पुनर्चक्रण नीति को लागू करने की मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य "सर्कुलर इकोनॉमी" को बढ़ावा देना और जल संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। इस नीति के तहत सीवेज और अपशिष्ट जल को शुद्ध कर औद्योगिक, कृषि और सार्वजनिक उपयोग के लिए पुनः इस्तेमाल किया जाएगा।

कृषि भूमि प्रबंधन के क्षेत्र में भी सुधार के संकेत देते हुए सरकार ने "तुकडेबंदी अधिनियम 1947" में संशोधन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य खेती योग्य भूमि के अत्यधिक विभाजन को रोकना और जमीनों के एकत्रीकरण को प्रोत्साहित करना है। संशोधन के बाद भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटने की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जा सकेगा, जिससे किसानों की उत्पादकता और आय दोनों में वृद्धि होगी।

सामाजिक क्षेत्र में राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कल्याण विभाग के तहत अनुदानित आश्रमशालाओं में कार्यरत गैर-शिक्षण कर्मचारियों को सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगति योजना (ACP) का लाभ देने की घोषणा की है। इस योजना से राज्यभर में लगभग 980 आश्रमशालाओं के कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है। निजी सूतगिरनियों को अब सहकारी सूतगिरनियों की तरह प्रति यूनिट 3 की बिजली सब्सिडी दी जाएगी। यह राहत "एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग नीति–2023-28" के अंतर्गत दी जाएगी। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सभी पावरलूम मालिकों को कपड़ा आयुक्तालय के पोर्टल पर छह माह के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र सरकार के इन निर्णयों से स्पष्ट है कि राज्य अब केवल औद्योगिक विकास पर नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन, पर्यावरणीय स्थिरता और शहरी पुनर्रचना पर भी समान रूप से ध्यान दे रहा है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से महाराष्ट्र की आर्थिक गति और नागरिक जीवन—दोनों में ही व्यापक परिवर्तन देखने को मिल सकता है।

न्यायिक सेवा में ठहराव पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय — अब संविधान पीठ तय करेगी निचली अदालतों के जजों के प्रमोशन और करियर असमानता का भविष्य

नई दिल्ली। देश की न्यायपालिका में लंबे समय से चली आ रही एक गंभीर समस्या — निचली अदालतों के न्यायाधीशों की पदोन्नति और करियर प्रगति में ठहराव — अब सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च स्तर पर विचार के लिए पहुंच गई है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेजने का फैसला सुनाया, जिससे लाखों न्यायिक अधिकारियों के भविष्य से जुड़ा यह मसला अब निर्णायक मोड़ पर पहुँच गया है। यह निर्णय न केवल न्यायिक प्रणाली के ढांचे में सुधार का संकेत देता है, बल्कि यह भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक नई दिशा की शुरुआत भी हो सकता है।

मामला 'अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ'

की याचिका से जुड़ा है, जिसमें अधीनस्थ अदालतों में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों, वेतनमान, और पदोन्नति की नीतियों को लेकर गंभीर असमानताओं का मुद्दा उठाया गया था। याचिका में कहा गया कि देशभर की निचली अदालतों में हजारों जज वर्षों की मेहनत के बावजूद उच्च पदों तक नहीं पहुँच पाते। कई अधिकारी ऐसे हैं जो 25 या 26 वर्ष की आयु में न्यायिक सेवा में प्रवेश करते हैं, और चार दशक की ईमानदार सेवा के बाद भी अतिरिक्त जिला जज के पद से आगे नहीं बढ़ पाते। यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत अन्याय है, बल्कि यह न्यायिक संस्थान की कार्यकुशलता और प्रेरणा को भी प्रभावित करती है।

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह समस्या किसी एक राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह लगभग पूरे भारत में निचली न्यायपालिका के अधिकारियों के सामने समान रूप से उपस्थित है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों से आए जवाब इस बात को स्पष्ट करते हैं कि न्यायिक सेवाओं में पदोन्नति की प्रणाली न तो एकसमान है और न ही न्यायपूर्ण। कई जगह सीनियरिटी का गलत मूल्यांकन, कोटा प्रणाली, और मूल्यांकन में पारदर्शिता की कमी के कारण योग्य अधिकारियों का मनोबल टूट रहा है।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गवई ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि "यह अत्यंत निराशाजनक है कि एक युवा न्यायिक अधिकारी, जो जोश और निष्ठा के साथ सेवा में आता है, वह तीस वर्षों तक न्यायपालिका को समर्पित करने के बाद भी शीर्ष पद तक नहीं पहुँच पाता। जब योग्यता के बावजूद अवसर सीमित हों, तो न केवल व्यक्ति की आकांक्षाएँ टूटती हैं, बल्कि संस्था की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है।"

बाढ़ और आपदा राहत में बड़ा कदम — असम और गुजरात को 708 करोड़, हरियाणा, मध्यप्रदेश और राजस्थान को अग्निशमन सेवाओं के लिए 904 करोड़ की मंजूरी

नई दिल्ली। देश में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने और प्रभावित राज्यों को शीघ्र राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने वर्ष 2024 में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित असम और गुजरात के लिए कुल 707.97 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मंजूर की है। यह राशि राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के माध्यम से राज्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रक्रिया में वर्ष की शुरुआत में राज्यों के पास उपलब्ध शेष राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) का 50 प्रतिशत समायोजित किया जाएगा। इस वितरण

के तहत असम को 313.69 करोड़ रुपये और गुजरात को 394.28 करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की पुनर्स्थापना, राहत और पुनर्वास कार्य तेजी से किए जा सकेंगे।

केंद्रीय समिति ने केवल बाढ़ राहत तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि देश में आपदा प्रबंधन और बचाव सेवाओं के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया। इसी कड़ी में हरियाणा, मध्यप्रदेश और राजस्थान के अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 903.67 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। इसमें 676.33 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की ओर से सहायता के रूप में शामिल हैं। हरियाणा को 117.19 करोड़, मध्यप्रदेश को 397.54 करोड़ और राजस्थान को 388.94 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य केवल आधुनिक उपकरणों और आपदा प्रबंधन संसाधनों की खरीद तक सीमित नहीं है। यह कदम राज्यों में अग्निशमन और आपदा राहत कार्यों की तत्परता, प्रशिक्षण और तात्कालिक प्रतिक्रिया प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए भी उठाया गया है। इससे प्राकृतिक आपदाओं के समय प्रभावी बचाव और राहत कार्यों को गति मिलेगी और जीवन और संपत्ति की हानि को न्यूनतम किया जा सकेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के माध्यम से यह सहयोग राज्य और केंद्र के बीच आपदा प्रबंधन में समन्वय को भी मजबूत करेगा। असम और गुजरात जैसे बाढ़ प्रवण राज्यों में बुनियादी ढांचे के सुधार और पुनर्वास कार्य जल्दी शुरू होने से प्रभावित जनजीवन को जल्द सामान्य किया जा सकेगा। वहीं हरियाणा, मध्यप्रदेश और राजस्थान में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार से औद्योगिक और शहरी इलाकों में आग और अन्य आपदाओं से निपटने की क्षमता बढ़ेगी।

मुंबई में पीएम मोदी की सौगातों की बरसात — मेट्रो लाइन, नवी मुंबई एयरपोर्ट और मुंबई वन ऐप का शुभारंभ, ब्रिटिश पीएम से मुलाकात

मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार से शुरू हो रहे दो दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं, जो न केवल शहर की यातायात व्यवस्था और तकनीकी क्षमता को बढ़ाएंगे, बल्कि युवाओं के कौशल विकास और आर्थिक प्रगति में भी मदद करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान मुंबई मेट्रो की लाइन-3 (एक्वा लाइन) के अंतिम चरण का उद्घाटन करेंगे, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का शुभारंभ करेंगे और मुंबई वन मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। इसके अलावा, वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रशीद स्टार्मर से भी मुलाकात करेंगे और भारत-यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Vision 2035) की प्रगति पर विचार करेंगे।

मुंबई मेट्रो की लाइन-3 को एक्वा लाइन के नाम से जाना जाता है और इसे 37,270 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है। यह 33.5 किलोमीटर लंबी लाइन कफ परेड से आरे जेवीएलआर तक फैली हुई है, जिसमें कुल 27 स्टेशन होंगे। यह लाइन नेहरू विज्ञान केंद्र, मुंबई सेंट्रल, कालबादेवी, हुतात्मा चौक, विधानभवन, महालक्ष्मी, चर्चगेट, सीएसएमटी, ग्रांट रोड, गिरगांव और कफ परेड जैसे महत्वपूर्ण केंद्रों से होकर गुजरेगी। मेट्रो के इस अंतिम चरण से रोजाना 13 लाख से अधिक यात्रियों को लाभ मिलने का अनुमान है। किराया संरचना भी यात्रियों के लिए सुलभ

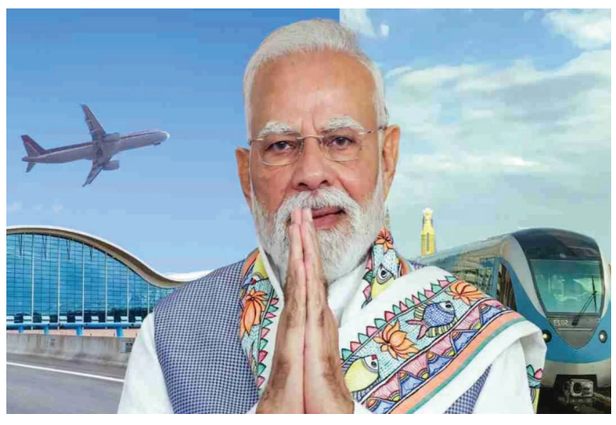

बनाई गई है, जिसमें 3 किलोमीटर तक की यात्रा का प्रारंभिक किराया 10 रुपये है और लंबी दूरी के लिए अधिकतम किराया 50-60 रुपये के बीच रखा गया है।

प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र सरकार के STEP प्रोग्राम का भी शुभारंभ करेंगे। यह कार्यक्रम युवाओं को उद्योग की आवश्यकताओं से जोड़ने और उनकी कौशल क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 400 सरकारी ITI और 150 तकनीकी हाई स्कूल शामिल हैं। कुल 2,500 नए ट्रेनिंग बैच चलेंगे, जिनमें 364 महिलाओं के लिए विशेष बैच होंगे। यह प्रोग्राम उभरती तकनीकों जैसे AI, IoT, EV, सोलर और 3D प्रिंटिंग में प्रशिक्षण देगा, जिससे युवाओं के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की सामाजिक और आर्थिक प्रगति को बल मिलेगा।

मुंबई वन मोबाइल ऐप भी प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह ऐप भारत का पहला मल्टी-मोड ट्रांसपोर्ट प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें 11 सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटर शामिल हैं। ऐप में मुंबई मेट्रो की लाइन 1, 2A, 3 और 7 के साथ-साथ मुंबई मोनोरेल, लोकल ट्रेन और BEST बस की सेवाएँ उपलब्ध होंगी। ठाणे, मीरा-भायंदर, कल्याण-डोंबिवली और नवी मुंबई की सेवाएँ भी ऐप में शामिल होंगी। यह डिजिटल टिकटिंग, रियल-टाइम अपडेट और SOS फीचर प्रदान करेगा, जिससे यात्रियों के लिए यात्रा सरल, सुरक्षित और पारदर्शी होगी।

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) के पहले चरण का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। यह एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और 3,700 मीटर लंबे रनवे सहित विकसित किया गया है, जिसकी कुल लागत लगभग 16,950 करोड़ रुपये है। पहले चरण के टर्मिनल की क्षमता 2 करोड़ यात्रियों की है, जबकि पूरे एयरपोर्ट की अंतिम क्षमता 9 करोड़ यात्रियों और 3.25 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो की होगी। यह एयरपोर्ट बड़े पैसेंजर विमान जैसे A380 की लैंडिंग और टेकऑफ के लिए सक्षम है।

दौरे के दौरान पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर भारत-यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी 'Vision 2035' की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस साझेदारी के तहत व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, जलवायु, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में 10 वर्षीय रोडमैप पर चर्चा होगी। दोनों नेता भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) के अवसरों पर विचार करेंगे और वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण साझा करेंगे। साथ ही, वे उद्योग विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और नवप्रवर्तकों से भी मुलाकात करेंगे, ताकि भारत-यूके आर्थिक साझेदारी को और मजबूत बनाया जा सके।

इस दौरे के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल महाराष्ट्र के नागरिकों को आधुनिक परिवहन सुविधाओं का तोहफा दिया है, बल्कि युवाओं के कौशल विकास, रोजगार सृजन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए मार्ग भी खोले हैं। मेट्रो लाइन, एयरपोर्ट और मुंबई वन ऐप जैसे प्रोजेक्ट्स से शहर की जीवनशैली और आर्थिक गतिशीलता में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है।

संपादकीय

गाजा में जगी युद्ध विराम की उम्मीद

आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की शांति का नोबेल पुरस्कार पाने की तीव्र आकांक्षा के बीच की गई पहल से गाजा में दो साल से जारी इस्राइल के निरंकुश हमलों पर रोक लगने की आस जगी है। मिस्र के शर्म अल-शेख रिसॉर्ट में अमेरिका की मध्यस्थता में शुरू हुई वार्ता ने दुनियाभर में भरोसा जगाया है कि अब गाजा संकट का समाधान निकल सकता है। वास्तव में दो साल से जारी इस्राइल-हमास संघर्ष में मानवता कराह रही है। हालांकि, इस संकट की शुरुआत हमास के क्रूर आतंकी हमले से ही हुई थी। दरअसल, यह संघर्ष 7 अक्तूबर, 2023 को हमास के आतंकवादियों द्वारा इस्राइल की धरती पर गए स्तब्धकारी क्रूर हमले के बाद शुरू हुआ था। इस जघन्य नरसंहार में इस्राइल व कुछ अन्य देशों के बारह सौ के करीब नागरिक मारे गए थे। इतना ही नहीं हमास के आतंकवादी 250 इस्राइली व अन्य देशों के लोगों को बंधक बनाकर ले गए थे ताकि इस्राइल पर वार्ता में दबाव बनाया जा सके। अभी कुछ जीवित बंधक तथा कुछ मृतकों के शव हमास के कब्जे में हैं, जिन्हें वह वार्ता में ढाल की तरह इस्तेमाल करता रहा है। इस घटनाक्रम को यहूदियों के सबसे बड़े नरसंहार के बाद दूसरा बड़ा खूनी दिन बताया गया था। जिसका जवाब इस्राइल ने गाजा को मटियामेट करके दिया, जिसमें हमास के आतंकवादियों समेत 67000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए। जिसमें अधिकांश आम नागरिक थे। इस्राइल के लगातार जारी घातक हमलों से गाजा आज खण्डहर में तब्दील हो गया है। बताया जाता है कि करीब 22 लाख गाजावासियों में ज्यादातर बेघर हैं और भूख से जूझ रहे हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त स्वतंत्र वरिष्ठ जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला था कि गाजा में इस्राइली हमलों की कार्रवाई नरसंहार की श्रेणी में आती है। मिस्र के शर्म अल-शेख रिसॉर्ट में अमेरिका की मध्यस्थता में शुरू हुई वार्ता के बाद कहा जा रहा है कि इस्राइल और हमास अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित 20-सूत्रीय योजना के कुछ हिस्सों को लेकर सहमत हो गए हैं। बहरहाल, इस्राइल व हमास के समझौते की ओर बढ़ने से हमास के कब्जे में रखे गए बंधकों की रिहाई की उम्मीद भी जगी है। हालांकि, इस समझौता वार्ता का एक विवादास्पद मुद्दा हमास का निरस्त्रीकरण भी है, जिसे हमास स्वीकारने को तैयार नहीं हो रहा था। वहीं गाजा के शासन से हमास को बाहर रखे जाने के मुद्दे का भी वार्ता के परिणामों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इस वार्ता को लेकर भारत ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। भारत ने ट्रंप की योजना को फलस्तीन और इस्राइली लोगों के लिये दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक व्यवहार्य मार्ग बताते हुए, इस पहल की सराहना की है। निस्संदेह, भारत की यह सक्रिय प्रतिक्रिया हाल के वर्षों में गाजा संघर्ष में युद्धविराम से संबंधित संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों पर मतदान से उसके बार-बार परहेज करने के बिल्कुल विपरीत है। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने ही भारत ने फलस्तीनी मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान और द्विराज्य विकल्प के क्रियान्वयन पर न्यूयॉर्क घोषणापत्र का समर्थन करने वाले संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। इस परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव तब देखा गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौ सितंबर को कतर पर हुए इस्राइली हमलों की निंदा की थी। हालांकि, उन्होंने इस बाबत हमलावर, इस्राइल का नाम लेने से परहेज किया था। इसमें दो राय नहीं कि ट्रंप की योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन देना स्पष्ट रूप से भारत और अमेरिका के संबंधों को पटरी पर लाने के एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। वैसे देखा जाए तो दिल्ली ने इस्राइल के मामले में काफी हद तक सावधानी बरती है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के बचाव के अधिकार का इस्राइल ने पुरजोर समर्थन किया था। भारत को उम्मीद है कि पश्चिम एशिया में उसकी यह पहल अशांत क्षेत्र में शांति बहाल होने पर फायदेमंद साबित हो सकती है।

बड़ी तेजी दिखा रहा है Pakistan ! US को Rare Earth Elements की पहली खेप निर्यात भी कर दी

> पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान उन्हें पाकिस्तान के दुर्लभ खनिजों का सैंपल दिखाया था। इस मुलाकात के चंद दिनों बाद ही अमेरिका को पहली खेप का निर्यात भी कर दिया गया।

लगभग दो दशकों से ठंडे पड़े अमेरिका–पाकिस्तान संबंधों में नई गर्माहट लाने की एक अप्रत्याशित कोशिश में पाकिस्तान ने हाल ही में दुर्लभ धातुओं (Rare Earth Elements) से युक्त खनिजों की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की है। इस्लामाबाद ने इसे "द्विपक्षीय सहयोग में ऐतिहासिक मील का पत्थर" बताते हुए दावा किया है कि यह सौदा दोनों देशों के बीच नई रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत है। सरकारी घोषणा के अनुसार, पाकिस्तान ने अमेरिकी कंपनी US Strategic Metals (USSM), जो मिसौरी स्थित एक निजी संस्था है, उसको $500 मिलियन के समझौते के तहत "एंटिमनी, कॉपर कंसंट्रेट और दुर्लभ पृथ्वी धातुओं" की पहली खेप भेजी है। हम आपको याद दिला दें कि यह समझौता सितंबर के आरंभ में पाकिस्तान की राज्य-नियंत्रित संस्था Frontier Works Organisation (FWO) के साथ हुआ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान उन्हें पाकिस्तान के दुर्लभ खनिजों का सैंपल दिखाया था। इस मुलाकात के चंद दिनों बाद ही अमेरिका को पहली खेप का निर्यात भी कर दिया गया। हम आपको बता दें कि अमेरिका इस समय चीन की एकाधिकार वाली पकड़ से निकलने की कोशिश कर रहा है जो उसने वैश्विक दुर्लभ धातु आपूर्ति श्रृंखला पर जमा रखी है। चीन की यह पकड़ न केवल ऑटोमोबाइल, रॉकेटरी और उन्नत

कंप्यूटिंग जैसी उद्योगों के लिए अहम है, बल्कि आधुनिक रक्षा उत्पादन का भी मूलाधार है। इसी परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान ने स्वयं को "विश्वसनीय और भरोसेमंद साझेदार" के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने कहा, "आज पाकिस्तान सुरक्षित और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण में अमेरिका का सच्चा सहयोगी बनकर आगे बढ़ा है।"

इसे भी पढ़ें: India-Pakistan Conflict | Donald Trump का फिर चौंकाने वाला बयान, 'मैंने शुल्कों के दम पर रुकवाया भारत-पाक युद्ध', खुद को बताया शांतिदूत

लेकिन विशेषज्ञों की नज़र में पाकिस्तान का यह दावा ज्यादा प्रचार और कम वास्तविकता पर आधारित है। दरअसल, जिन धातुओं— नियोडिमियम और प्रासियोडिमियम का ज़िक्र पाकिस्तान ने किया है, वे सीधे तौर पर नहीं बल्कि जटिल यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। इन धातुओं को अयस्क से शुद्ध रूप में अलग करने में वर्षों या दशकों का समय लगता है। वर्तमान में स्वयं अमेरिका के पास भी इन धातुओं को परिष्कृत करने की पूरी क्षमता नहीं है। अमेरिका की एकमात्र सक्रिय कंपनी MP Materials कैलिफ़ोर्निया के Mountain Pass Mine से अयस्क निकालती है, लेकिन उसे अंतिम प्रक्रिया के लिए चीन भेजना पड़ता है।

यानि, पाकिस्तान जो भेज रहा है वह कच्चा अयस्क है, तैयार धातु नहीं है। देखा जाये तो अमेरिका के लिए यह कोई तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि चीन पर निर्भरता से बचने की दीर्घकालिक रणनीति का एक आरंभिक कदम मात्र है। इसलिए पाकिस्तान का यह "निर्यात" आर्थिक से ज़्यादा कूटनीतिक प्रतीकात्मकता रखता है।

इसके अलावा, अमेरिका के लिए यह समझौता एक रणनीतिक सुरक्षा कवच जैसा है जिससे वह बाहरी निर्भरता से आंशिक रूप से मुक्त होकर अपनी रक्षा, ऊर्जा और उच्च-प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल सुनिश्चित कर सके। वहीं पाकिस्तान के लिए यह एक कूटनीतिक पुनर्जागरण का अवसर है, खासकर तब जब चीन के साथ उसके संबंधों में संतुलन साधना अब चुनौती बन चुका है।

हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उसकी धरती में लगभग 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के खनिज संसाधन हैं, जो उसे "वैश्विक खनिज अर्थव्यवस्था की उभरती शक्ति" बना सकते हैं। लेकिन इन दावों पर संदेह है, क्योंकि न तो पाकिस्तान के पास इन धातुओं के निष्कर्षण और प्रसंस्करण की तकनीकी क्षमता है, न ही निवेश माहौल इतना स्थिर है कि विदेशी कंपनियाँ दीर्घकालिक साझेदारी को लेकर आश्वस्त हों।

हम आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान और USSM के बीच हुआ यह समझौता "साझा मूल्य श्रृंखला विकास" का ढांचा प्रस्तुत करता है— जिसमें खोज, अयस्क प्रसंस्करण, सांद्रण उत्पादन और भविष्य में पाकिस्तान में ही रिफाइनरी स्थापित करने की योजना शामिल है। यदि यह परियोजना सचमुच आगे बढ़ती है, तो यह पाकिस्तान की खनिज अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकती है। परंतु इतिहास बताता है कि इस्लामाबाद की अधिकांश विदेशी साझेदारियाँ या तो राजनीतिक अस्थिरता के कारण ठप पड़ गईं या सैन्य प्राथमिकताओं के बोझ तले दब गईं।

इस परिप्रेक्ष्य में, यह सौदा भी कई विशेषज्ञों के लिए "डॉलर डिप्लोमेसी" का नया अध्याय है— जहाँ पाकिस्तान अपनी आर्थिक मजबूरियों को भुनाकर भू-राजनीतिक जगह तलाशने की कोशिश कर रहा है। यह पहल जितनी अमेरिका की "सप्लाई चेन सुरक्षा" की ज़रूरत से जुड़ी है, उतनी ही पाकिस्तान की "राजनैतिक प्रासंगिकता" बहाल करने की कोशिश भी है।

कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का यह निर्यात किसी वास्तविक औद्योगिक छलांग से ज़्यादा राजनैतिक संदेश है कि वह अब चीन के साए से बाहर निकलकर बहुध्रुवीय कूटनीति की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। अमेरिका के लिए यह सौदा भले छोटे स्तर पर हो, पर रणनीतिक दृष्टि से एक दीर्घकालिक निवेश है। यह एक ऐसा साझेदार तैयार करने की कोशिश है जो भविष्य में चीन की जगह आंशिक रूप से भर सके।

बहरहाल, यह साझेदारी न तो अभी "ऐतिहासिक" है और न ही "परिवर्तनकारी", पर यह निश्चित रूप से उस पुराने संवाद की वापसी है जो कभी वॉशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच टूटा था। अब देखना यह होगा कि क्या यह "खनिज कूटनीति" दो दशकों की दूरी को पाट पाएगी, या बस एक और अस्थायी चमक बनकर रह जाएगी।

प्रेरणा

विश्वास की वह सीढ़ी जिसने इतिहास बदल दिया

अमेरिका के उस दौर में, जब इंसानों को उनके रंग के आधार पर बाँट दिया गया था, जब काले लोगों को इंसान से ज़्यादा एक वस्तु समझा जाता था, उसी दुनिया में जन्मे एक बच्चे ने यह नहीं सोचा था कि उसका रंग उसकी किस्मत तय करेगा। वह बच्चा था—मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उसकी आत्मा में एक गहरी आस्था थी कि न्याय और समानता केवल शब्द नहीं, बल्कि ईश्वर की सबसे सुंदर देन हैं। लेकिन समाज उस समय इस सच्चाई को सुनने के लिए तैयार नहीं था। सड़कों पर 'गोरों के लिए' और 'काले लोगों के लिए' लिखे बोर्ड झूलते थे। स्कूल, बसें, रेस्टोरेंट, पार्क—सब जगह दीवारें थीं, जो रंग के नाम पर इंसानियत को बाँट रही थीं।

मार्टिन लूथर किंग ने बचपन से ही यह सब देखा। एक बार जब वे छोटे थे, तो उनके दोस्त के पिता ने उन्हें खेलने से मना कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे काले थे। उस दिन उनका दिल टूट गया, लेकिन उनके पिता ने कहा—"बेटा, कभी यह मत मानना कि तुम किसी से कम हो। तुम्हारा रंग ईश्वर की रचना है, और उसकी हर रचना में एक उद्देश्य छिपा है।" वह बात मार्टिन के दिल में गहराई तक उतर गई। उन्होंने तय किया कि अगर ईश्वर ने उन्हें काला बनाया है, तो शायद उसी रंग में न्याय की सबसे बड़ी कहानी लिखने की जिम्मेदारी भी दी है। समय बीता, और एक दिन उन्होंने देखा कि उनके अपने लोग गोरों के अत्याचारों से टूट चुके हैं। वे मान चुके थे कि यह दुनिया कभी नहीं बदलेगी। तब मार्टिन ने एक संकल्प लिया—"मैं इस दुनिया से

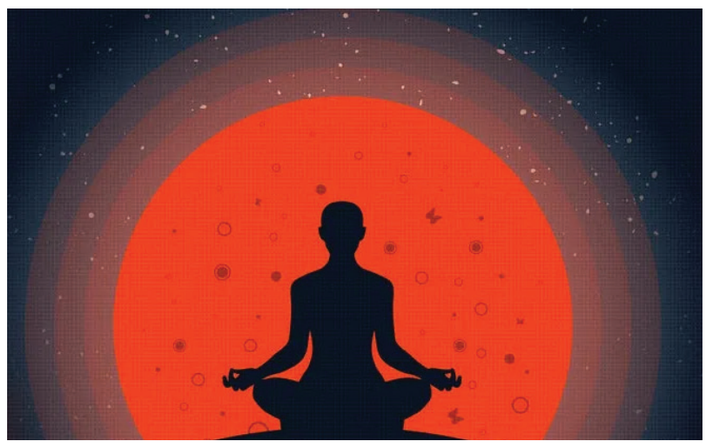

नफरत मिटाऊँगा, लेकिन नफरत से नहीं, प्रेम से।" उन्होंने रंगभेद के खिलाफ आवाज़ उठाई, मगर उनके शब्दों में तलवार की धार नहीं थी, उनमें प्रार्थना की गहराई थी। उन्होंने कहा, "मैं किसी से इसलिए नहीं लड़ रहा कि उसे हराऊँ, मैं इसलिए खड़ा हूँ ताकि हम सब जीत सकें।"

शुरुआत में वे अकेले थे। सड़कों पर उनका मज़ाक उड़ाया गया, जेलों में ठूंसा गया, धमकियाँ दी गईं, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उन्होंने लोगों से कहा—"जब आपको पूरी सीढ़ी नहीं दिख रही हो, तब भी पहला कदम विश्वास के साथ बढ़ाइए।" यही विश्वास धीरे-धीरे एक चिंगारी से ज्वाला बना। उनकी एक पुकार "I have a dream" यानी "मेरे पास एक सपना है" इतिहास का सबसे शक्तिशाली वाक्य बन गया। उन्होंने उस भाषण में एक ऐसे भविष्य की कल्पना की, जहाँ एक दिन उनके बच्चे और गोरे बच्चों के बीच कोई भेद नहीं होगा; जहाँ हर व्यक्ति को उसके कर्म से आंका जाएगा, उसके रंग से नहीं।

यह सपना केवल उनका नहीं रहा, यह करोड़ों दिलों का सपना बन गया। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे, हज़ारों ने जेलें भरीं, और दुनिया ने देखा कि एक निहत्थे आदमी के शब्द गोलियों से ज्यादा ताकतवर साबित हुए। आखिरकार, वर्षों की जंग के बाद, अमेरिका की संसद ने रंगभेद की नीति को खत्म किया और सबको समान अधिकार दिए। जब जीत मिली, तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा, "डॉ. किंग, आपने इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी यह कैसे कर दिखाया?" मार्टिन मुस्कराए और बोले, "सिर्फ विश्वास के बल पर। जब मुझे सीढ़ियाँ नहीं दिख रही थीं, तब मैंने पहले पायदान पर विश्वास के साथ कदम रखा, और धीरे-धीरे सारी सीढ़ियाँ पार कर लीं।" उनका यह उत्तर आज भी हर संघर्षशील आत्मा को दिशा देता है। यह सिखाता है कि विश्वास कोई मूर्त वस्तु नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो हमें अंधेरे में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। जब हालात हमारे खिलाफ हों, जब राहें बंद लगें, जब पूरी दुनिया कहे कि यह असंभव है, तभी विश्वास की सीढ़ी पर पहला कदम रखना सबसे बड़ा साहस होता है।

मार्टिन लूथर किंग ने दुनिया को यह दिखाया कि सच्चा विश्वास केवल ईश्वर में नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य की पवित्रता में भी होता है। आज भी जब कोई व्यक्ति टूटने लगता है, जब कोई सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो कहीं न कहीं मार्टिन की वह आवाज़ गूंज उठती है—"मैंने पहले पायदान पर विश्वास के साथ कदम रखा।"

वह आवाज़ समय के पार चली गई है, लेकिन उसकी गूंज आज भी उतनी ही गहरी है। क्योंकि अंततः इतिहास उसी के आगे झुकता है, जो अंधेरे में भी प्रकाश को देखने का साहस रखता है, जो विश्वास की सीढ़ी पर पहला कदम रखने से नहीं डरता।

ताकि दवा जहर बन फिर से मासूमों की मौत न बने

दो राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से जुड़ी बच्चों की मौत की घटनाएं देश की दवा नियामक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। यह केवल एक चिकित्सा त्रुटि या आकस्मिक दुर्घटना नहीं, बल्कि उस तंत्र की विफलता का प्रतीक है जिस पर जनता अपने जीवन की रक्षा के लिए भरोसा करती है। दवा जैसी जीवनदायी वस्तु में भी जब लालच, लापरवाही या भ्रष्टाचार घुसपैठ कर जाते हैं तो वह अमृत भी विष बन जाता है। बच्चों की मासूम जानें जब घटिया या मिलावटी दवा के कारण चली जाती हैं, तो यह केवल परिवारों की नहीं, बल्कि पूरे समाज की नैतिकता एवं विश्वास की मृत्यु होती है। कफ सिरप में पाए गए विषैले तत्व-जैसे डाइएथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल, पहले भी कई देशों में सैकड़ों बच्चों की जान ले चुके हैं। फिर भी बार-बार ऐसे हादसे होना इस बात का प्रमाण है कि भारत की दवा नियामक व्यवस्था में संरचनात्मक खामियां बनी हुई हैं। सवाल है कि पिछली गलतियों से क्या सीखा गया? भारत में बने कफ सिरप पहले भी सवालों में आ चुके हैं। 2022 में गाम्बिया में कई बच्चों की मौत के बाद डब्ल्यूएचओ ने एक भारतीय कंपनी के कफ सिरप को लेकर चेतावनी जारी की थी। इसके बाद भी कई और जगहों से इसी तरह की शिकायत आई। दवाओं के उत्पादन में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। करीब 200 देशों में यहां से दवाएं निर्यात होती हैं और जेनेरिक दवाएं सबसे ज्यादा यहीं बनती हैं। इन उपलब्धियों के बीच इन दो प्रमुख राज्यों में कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत शर्मनाक एवं त्रासदीपूर्ण है। इससे स्पष्ट है कि दवा के क्षेत्र में जिस तरह की निगरानी, मानक और सुरक्षा उपायों की जरूरत है, उसमें कोताही बरती जा रही है। दवा के रूप में जहर धडल्ले से मासूमों की मौत का कारण बन रहा है। इस घटना सामने आने के बाद कार्रवाई का दौर भले ही जारी है। दवाएं वापस ली गई हैं, केस दर्ज हुआ है और नैशनल रेगुलेटर अथॉरिटी ने कई राज्यों में जांच की है। इन घटनाओं से साफ है कि दवा निर्माण की प्रक्रिया में कच्चे माल के स्रोत से लेकर तैयार उत्पाद की गुणवत्ता जांच तक हर स्तर पर लापरवाही व्याप्त है। कई कंपनियां लागत घटाने के लिए औद्योगिक ग्रेड के सॉल्वेंट या रसायनों का प्रयोग कर लेती हैं जो मानव उपभोग के लिए निषिद्ध होते हैं। वहीं निरीक्षण और परीक्षण की सरकारी व्यवस्था न केवल कमज़ोर है बल्कि अक्सर प्रभावशाली कंपनियों के दबाव में निष्क्रिय भी हो जाती है। राज्य और केंद्र स्तर के दवा-नियामक विभागों में पर्याप्त संसाधन और तकनीकी क्षमता का अभाव है, जिससे समय पर निगरानी और सैंपल परीक्षण संभव नहीं हो पाता। जब निरीक्षण औपचारिकता बन जाए और रिपोर्टें खरीद-फरोख्त की वस्तु बन जाएं, तब ऐसी त्रासदियां स्वाभाविक हैं। तमिलनाडु की दवा कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप के नमूने में 48.6 प्रतिशत डाई एथिलीन ग्लाइकॉल मिला है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार इसकी मात्रा 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह एक खतरनाक इंडस्ट्रियल केमिकल है, जिसका इस्तेमाल गाड़ियों और मशीनों में होता है। इसकी वजह से पीड़ित बच्चों की किडनी फेल हो गई।

इसे भी पढ़ें: कफ सिरप से बच्चों की मौत की खबरें चिंताजनक, दवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी रखना सबसे बड़ी जरूरत

इन घटनाओं ने न केवल स्वास्थ्य प्रशासन की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाई है बल्कि भारत की वैश्विक छवि पर भी धब्बा लगाया है। पिछले वर्षों में अफ्रीकी देशों में भी भारतीय सिरप से हुई मौतों के बाद कई देशों ने हमारे फार्मा उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया था। अब घरेलू स्तर पर घटित ऐसी घटनाएं यह दर्शाती हैं कि हमने उन हादसों से कोई सबक नहीं लिया। दुनिया के सबसे बड़े जेनेरिक दवा उत्पादक देश के रूप में भारत को यह मानना होगा कि केवल उत्पादन की मात्रा नहीं, बल्कि गुणवत्ता ही हमारी असली ताकत होनी चाहिए। इस संकट का सबसे पीड़ादायक पहलू यह है कि इसका शिकार वे मासूम बच्चे बने जिनकी प्रतिरोधक क्षमता अभी विकसित नहीं हुई थी और जिनकी जीवन रक्षा का उत्तरदायित्व समाज और राज्य पर है। इन मौतों की नैतिक जिम्मेदारी केवल दोषी कंपनियों पर नहीं, बल्कि उस पूरे तंत्र पर है जिसने नियमन और नैतिकता की आंखें मूंद लीं। दवाओं में मिलावट या गलत प्रमाणपत्र देना कोई साधारण अपराध नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ किया गया घोर अपराध है। इस पर कड़े से कड़ा दंड होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी निर्माता या अधिकारी ऐसी हरकत करने से पहले सौ बार सोचे।

भारत के फार्मास्युटिकल मार्केट का आकार लगभग 60 अरब डॉलर है। इसका बड़ा हिस्सा छोटी कंपनियों के पास है। सीडीएसीओ ने इस साल अप्रैल की अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ज्यादातर छोटी और मझोली कंपनियों की दवाएं जांच में तयशुदा मानक से कमतर पाई गईं।

इस जांच में 68 प्रतिशत एमएसएमई फेल हो गई थीं। इससे पहले, जब केंद्रीय एजेंसी ने 2023 में जांच की, तब भी 65 प्रतिशत कंपनियों की दवाएं सब-स्टैंडर्ड मिली थीं। प्रश्न है कि यह तथ्य सामने आने के बाद आखिर सरकार क्या सोच कर इन दवाओं को बाजार में विक्रय क्यों जारी रहने दिया? क्यों ऐसे हादसे होने दिये जाते रहे? यह आवश्यक है कि दवा उद्योग में कच्चे माल की ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित की जाए, हर बैच की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो और दवाओं के मानक अंतरराष्ट्रीय स्तर के हों। केंद्र और राज्य सरकारों को ड्रग इंस्पेक्टरों की संख्या और प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ानी चाहिए। हर कंपनी के लाइसेंस नवीनीकरण के समय उसकी पिछली गुणवत्ता रिपोर्ट और परीक्षण परिणामों की समीक्षा की जानी चाहिए। जिन कंपनियों ने सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया है, उनके लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिए जाने चाहिए और शीर्ष प्रबंधन को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। केवल प्रशासनिक कार्रवाई पर्याप्त नहीं, बल्कि इन मामलों में आपराधिक जिम्मेदारी तय करना भी जरूरी है।

अभियान

सावित्री और सत्यवान की अमर गाथा: जब प्रेम ने मृत्यु को भी पराजित किया

प्राचीन भारत की धरती पर जब धर्म, प्रेम और निष्ठा ही जीवन का आधार हुआ करते थे, उसी युग में एक ऐसी कथा जन्मी जिसने युगों-युगों तक स्त्री के अटूट प्रेम और विश्वास को अमर कर दिया। यह कथा है सावित्री और सत्यवान की — एक ऐसी प्रेम गाथा जिसने न केवल मृत्यु के कठोर सत्य को पराजित किया, बल्कि यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम देवताओं को भी झुकने पर विवश कर देता है।

मद्र देश के राजा अश्वपति धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे, परंतु उनके जीवन में एक ही अभाव था — संतान का। उन्होंने वर्षों तक देवी सावित्री की उपासना की और तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें वरदान दिया कि उन्हें एक तेजस्विनी कन्या प्राप्त होगी। समय आने पर रानी ने एक ऐसी कन्या को जन्म दिया, जिसकी आँखों में तेज और मुख पर दिव्यता थी। उसका नाम देवी के नाम पर रखा गया — सावित्री।

सावित्री न केवल रूपवती थी, बल्कि उसका हृदय धर्म और करुणा से भरा हुआ था। जब विवाह योग्य आयु आई, तो राजा अश्वपति ने अनेक राजकुमारों के प्रस्ताव प्राप्त किए, पर कोई भी सावित्री के योग्य नहीं लगा। तब पिता ने कहा, "पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो।" सावित्री ने पिता की आज्ञा पाकर अनेक तीर्थों की यात्रा की और एक वन में सत्यवान नामक युवक से मिली। सत्यवान का जीवन सादगी और सेवा में बीतता था। वह अपने अंधे माता-पिता के साथ वन में रहता था, सत्य, धर्म और करुणा का साक्षात स्वरूप था। सावित्री ने उसी क्षण निश्चय किया कि यही उसका जीवनसाथी होगा।

जब वह पिता के पास लौटी और सत्यवान से विवाह की इच्छा प्रकट की, तभी वहाँ देवर्षि नारद आए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, "राजन, सत्यवान जितना सद्गुणी है, उतना ही दुर्भाग्यशाली भी, क्योंकि उसके जीवन का केवल एक वर्ष शेष है।" यह सुनते ही राजा अश्वपति व्याकुल हो उठे और बोले, "पुत्री, मैं तुम्हें दुख के मार्ग पर नहीं भेज सकता।" पर सावित्री ने शांत स्वर में कहा, "पिता, स्त्री का एक बार किया गया चयन उसके धर्म का आधार होता है। मैंने सत्यवान को अपने मन, वचन और कर्म से पति के रूप में स्वीकार किया है। अब पीछे हटना मेरे धर्म के विरुद्ध होगा।" सावित्री के इस दृढ़ संकल्प के आगे पिता झुक गए। विवाह हुआ और सावित्री सत्यवान के साथ वन में चली गई। वहाँ वह अपने अंधे सास-ससुर की अत्यंत श्रद्धा से सेवा करती थी। समय बीतता गया और वह दिन आया जिसे नारद ने बताया था। उस दिन सावित्री ने निर्जल व्रत रखा। उसने अपने मन को ईश्वर में एकाग्र किया और पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। जब सत्यवान लकड़ी काटने वन में गए, तो सावित्री भी उनके साथ गई। दोपहर होते-होते सत्यवान को चक्कर आने लगे और वे गिर पड़े। सावित्री ने उन्हें अपनी गोद में लिया। उसी समय आकाश से प्रकाश की एक रेखा उतरी — यमराज प्रकट हुए।

यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, "देवी, तुम्हारे पति का जीवन पूर्ण हुआ। अब मैं इन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ।" सावित्री ने नम्र स्वर में कहा, "प्रभु, यदि मृत्यु ही सत्य है, तो पतिव्रता धर्म भी उतना ही सत्य है। जहाँ मेरे पति जाएंगे, वहाँ तक जाना मेरा धर्म है।" यमराज मुस्कराए, किंतु अनुमति नहीं दी। सावित्री उनके पीछे-पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, "देवी, यह मृत्यु का मार्ग है, वापस लौट जाओ।" सावित्री ने उत्तर दिया, "जहाँ तक मेरे पति के पग पड़े हैं, वहाँ तक मेरे धर्म का भी अधिकार है।" यमराज उनकी दृढ़ता और भक्ति से प्रभावित हुए और बोले, "तुम्हें एक वर देता हूँ, जो चाहो मांगो।" सावित्री ने कहा, "मेरे सास-ससुर अंधे हैं, उन्हें दृष्टि मिल जाए।" यमराज ने वर दे दिया और आगे बढ़े। सावित्री फिर उनके साथ चलने लगी। यमराज ने दूसरी बार कहा, "अब लौट जाओ देवी।" सावित्री ने कहा, "पति के बिना लौटना अधर्म होगा।" यमराज प्रसन्न हुए और बोले, "एक और वर मांगो।" सावित्री बोलीं, "मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए।" यमराज ने दूसरा वर भी दे दिया।

सावित्री फिर नहीं रुकीं। अब यमराज ने तीसरी बार कहा, "अब तुम लौट जाओ, देवी। तुमने जो चाहा, सब पा लिया।" सावित्री ने बड़ी विनम्रता से कहा, "यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे सौ पुत्रों की माँ बनने का वरदान दें।" यमराज मुस्कराए, बोले, "तथास्तु।"

परंतु सावित्री का बुद्धिमान मन चुप नहीं था। उसने कहा, "हे धर्मराज, आपने मुझे सौ पुत्रों की माँ बनने का वर दिया, पर मैं अपने पति के बिना माँ कैसे बन सकती हूँ?" यमराज उनके तर्क, भक्ति और अदम्य निष्ठा से विस्मित हो गए। उन्होंने अपने पाश को खोला और बोले, "देवी, तुम्हारे समान पतिव्रता स्त्री न पहले हुई, न आगे होगी। मैं तुम्हारे पति को जीवनदान देता हूँ।"

उसी क्षण सत्यवान की देह में चेतना लौट आई। सावित्री की आँखों में कृतज्ञता के आँसू थे। वे दोनों वन से लौटे तो देखा कि उनके सास-ससुर को दृष्टि मिल चुकी है और खोया हुआ राज्य भी वापस आ गया है। वह दिन केवल एक परिवार की जीत नहीं थी, बल्कि नारी की शक्ति, निष्ठा और प्रेम की विजय का प्रतीक बन गया।

उस दिन से ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत मनाया जाने लगा। स्त्रियाँ सावित्री की तरह अपने पति के दीर्घायु जीवन की कामना करती हैं, वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं, जो अमरता और स्थायित्व का प्रतीक है।

सावित्री और सत्यवान की कथा केवल एक पौराणिक प्रेम कहानी नहीं है, यह भारतीय संस्कृति की आत्मा में गूँजने वाली वह ध्वनि है, जो बताती है कि प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि धर्म का स्वरूप है। यह सिखाती है कि जब विश्वास और निष्ठा साथ हों, तो मृत्यु जैसी शक्ति भी नारी के संकल्प के आगे झुक जाती है। सावित्री ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम अमर होता है — और उसका प्रकाश काल, मृत्यु और अंधकार से परे भी जगमगाता रहता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

पद्मश्री डॉ. गणपत पटेल की सफलता गाथा : साधारण शुरुआत से विश्वस्तरीय उद्योगपति और शिक्षा क्षेत्र के एक दूरदर्शी नेता तक का सफर

गणपत यूनिवर्सिटी में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के आयोजन से पद्मश्री डॉ. गणपत पटेल की समृद्ध विरासत उजागर होगी

गांधीनगर, 07 अक्टूबर : उत्तर गुजरात के मेहसाणा जिले के भुणाव गांव में एक साधारण शुरुआत से लेकर कैलिफोर्निया में अध्ययन तक डॉ. गणपत पटेल की सफलता गाथा प्रेरणादायी है। पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉ. गणपत पटेल ने शिक्षा क्षेत्र में अपने स्वप्न को साकार करने के लिए 'गणपत यूनिवर्सिटी' की स्थापना की। वे एक दूरदर्शी नेता हैं, जो अपने बहुमूल्य योगदान से समाज को सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं।

गणपत यूनिवर्सिटी में वीजीआरसी का आयोजन

राज्य सरकार की नई पहल के रूप में उत्तर गुजरात क्षेत्र के लिए 'वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस' (वीजीआरसी) का आयोजन मेहसाणा की गणपत यूनिवर्सिटी में होने जा रहा है। गणपत यूनिवर्सिटी नवाचार का एक प्रतिष्ठित केंद्र है। इस दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में उद्योग और शिक्षा क्षेत्र के अग्रणी महानुभाव एक साथ, एक मंच पर इकट्ठे होंगे और सेमिनार एवं पैनल चर्चाओं के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।

उत्कृष्टता का सफर

12 जनवरी, 1945 को मेहसाणा के भुणाव गांव में जन्मे डॉ. पटेल ने अपनी शिक्षा की शुरात गांव के प्राथमिक स्कूल की। इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद के एम.जी. साइंस कॉलेज में पढ़ाई पूरी की और इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। वहां उन्होंने आईयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी और बाद में 1969 में कैलिफोर्निया की पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, पोमोना से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की।

डॉ. पटेल को मिले सम्मान और उनके मूल्य

डॉ. पटेल को शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2019 में साहित्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके अलावा, उन्हें अमेरिका की 'अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन' की ओर से लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड और काल पोली यूनिवर्सिटी, पोमोओ की ओर से 2018 में डिस्टिंग्विश एलुमनस अवॉर्ड से नवाजा गया।

डॉ. पटेल ने अपने करियर की शुरुआत डिजाइन इंजीनियर के रूप में की और अमेरिका की कई अग्रणी कंपनियों के साथ कार्य किया, जिनमें यूएस एविएशन इंडस्ट्री, लॉकहीड (अजूजा), कल्वर सिटी में एबोट ट्रांजिस्टर लैब और जानी मानी कंप्यूटर सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बरोज कॉर्पोरेशन शामिल हैं। हालांकि, उनका स्वप्न एक उद्यमी बनने का था। 1978 में उन्होंने चेरोकी इंटरनेशनल की स्थापना की, जो आगे चलकर एक सफल वैश्विक कंपनी बनी। फिर 2004 में उन्होंने इस कंपनी को जनरल इलेक्ट्रिक (जीई) को बेच दिया। शिक्षा के स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने 2005 में 'गणपत यूनिवर्सिटी' की स्थापना की, ताकि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और सामाजिक परिवर्तन लाया जा सके। आज, गणवत यूनिवर्सिटी उनके विजन और समर्पण का प्रतीक बन गई है। यूनिवर्सिटी का परिसर 300 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, नवाचार केंद्र, डिजिटल कक्षाएं और पर्यावरण-अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। गुजरात सरकार ने इसे उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) के रूप में मान्यता दी है, साथ ही इसे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल (एनएएसी) से 'ए' ग्रेड और क्वाक्वेरेली साइमंड्स-क्यूएस आई-जीएयूजीई की ओर से डायमंड रेटिंग भी प्राप्त है।

गणपत यूनिवर्सिटी माननीय प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत@2047' के विजन और गुजरात सरकार के ज्ञान-आधारित, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य का समर्थन करती है। आज के उद्योगों के लिए प्रशिक्षण और नए कौशल प्रदान करने के लिए यूनिवर्सिटी विभिन्न सेक्टर स्कूल काउंसिल और एनएसडीसी इंटरनेशनल के साथ निकटता से जुड़कर कार्य कर रही है। यूनिवर्सिटी ने टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, एलान्फोचिप्स, टीसीएस, बॉश रेक्सरोथ, बजाज ऑटो और एमक्योर फार्मा जैसी कंपनियों के साथ गहन साझेदारी की है, जिसके चलते विद्यार्थियों को उद्योगों से संबंधित वास्तविक अनुभव प्राप्त करने में मदद मिलती है। गणपत यूनिवर्सिटी गुजरात का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो मरीन इंजीनियरिंग में बी.टेक. और नॉटिकल साइंस में बीएससी जैसे मैरीटाइम कार्यक्रमों की पेशकश करता है। इसमें एक अनोखा शिप-इन-कैम्पस और 360 डिग्री नेविगेशन सिम्युलेशन सेंटर है, जिसे नौवहन महानिदेशालय की ओर से ए-1 ग्रेड प्राप्त हुआ है।

आगामी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में शिक्षा और उद्यमिता के प्रति डॉ. गणपत पटेल के जीवनभर के समर्पण को एक बार फिर उजागर किया जाएगा। गणपत यूनिवर्सिटी परिसर में इस भव्य आयोजन के साथ ही डॉ. पटेल की सफलता गाथा सभी के लिए प्रेरणादायी बनेगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में व्याप्त चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 894 किलोमीटर बढ़ेगा

- 24,634 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत वाली परियोजनाएं 2030-31 तक पूरी होंगी
- Posted On: 07 OCT 2025 3:09PM by PIB Delhi
- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2175831
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज रेल मंत्रालय की 24,634 करोड़ रुपये के परिव्यय की चार परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें:

I.महाराष्ट्र में वर्धा - भुसावल के बीच 314 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी लाइन
II.महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 84 किलोमीटर लंबी गोंदिया-डोंगरगढ़ चौथी लाइन
III.गुजरात और मध्य प्रदेश में 259 किलोमीटर लंबी वडोदरा-रतलाम तीसरी और चौथी लाइन
IV.और, मध्य प्रदेश में 237 किलोमीटर लंबी इटारसी-भोपाल-बीना चौथी लाइन शामिल हैं

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्यों के 18 जिलों में व्याप्त इन चार परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 894 किलोमीटर की वृद्धि होगी।

स्वीकृत मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 3,633 गांवों, जिनकी जनसंख्या लगभग 85 लाख 84 हजार है, तथा दो आकांक्षी जिलों, विदिशा और राजनांदगांव तक संपर्क बढ़ेगा।

लाइन क्षमता में बढ़ोत्तरी से गतिशीलता बढ़ेगी, जिससे भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा। मल्टी ट्रैकिंग (पटरियों की संख्या बढ़ाना) प्रस्ताव परिचालन सुगम बनाने और भीड़भाड़ कम करने के लिए लाया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप इन परियोजनाओं से क्षेत्र के लोगों का व्यापक विकास होगा, वे आत्मनिर्भर बनेंगे और उनके लिए रोज़गार/स्वरोज़गार के अवसर बढ़ेंगे।

पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार इन परियोजनाओं का उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारक परामर्श द्वारा मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाना है। ये परियोजनाएं लोगों, वस्तुओं और सेवाओं को निर्बाध संपर्क प्रदान करेंगी।

परियोजना खंड सांची, सतपुड़ा बाघ अभयारण्य, प्रागैतिहासिक मानव जीवन के प्रमाणों और प्राचीन शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका शैलाश्रय, हज़ारा जलप्रपात, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान आदि प्रमुख स्थलों को भी रेल संपर्क प्रदान करेगा, जो देश भर के पर्यटकों को आकर्षित करेगा।

यह कोयला, कंटेनर, सीमेंट, फ्लाई ऐश, खाद्यान्न, इस्पात आदि वस्तुओं के परिवहन के लिए भी आवश्यक मार्ग है। पटरियों की संख्या बढ़ाए जाने से प्रति वर्ष 78 मिलियन टन की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी। रेलवे के पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन माध्यम होने के कारण यह देश के जलवायु लक्ष्यों और परिचालन लागत कम करने, तेल आयात (28 करोड़ लीटर) में कमी लाने और कार्बन उत्सर्जन 139 करोड़ किलोग्राम कम करने में मदद करेगा, जो छह करोड़ वृक्षारोपण के बराबर है।

स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत अहमदाबाद मण्डल द्वारा स्वच्छ स्टेशन, स्वच्छ रेलगाड़ी एवं स्वच्छ पटरी पर विशेष ध्यान

पश्चिम रेलवे का अहमदाबाद मण्डल 01 से 15 अक्टूबर, 2025 तक स्वच्छता पखवाड़ा 2025 मना रहा है। इस दौरान स्टेशनों, कार्यालयों और ट्रेनों में स्वच्छता, सफाई और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

पखवाड़ा के दौरान अहमदाबाद मण्डल के प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्मों, सर्कुलेटिंग क्षेत्रों और यात्री सुविधाओं की सघन सफाई की गई। कूड़ेदानों की उपलब्धता एवं उनके रखरखाव का सत्यापन किया गया, वहीं नालियों, शौचालयों, पहुँच मार्गों, पैदल ऊपरी पुलों और प्रतीक्षालयों की गहन सफाई की गई। प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए गए तथा सूखे एवं गीले कचरे हेतु अलग-अलग डस्टबिन की व्यवस्था की गई। हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सौर

ऊर्जा उपकरणों के संचालन और रखरखाव की जाँच की गई। इसी प्रकार, स्वच्छता और दुर्गंध नियंत्रण के लिए स्टेशनों पर नालियों और शौचालयों की सफाई सुनिश्चित की गई। ट्रेन वाशिंग लाइनों पर विशेष सफाई अभियान चलाए गए, जिनमें शौचालयों, गैंगवे और वेस्टिब्यूल क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। अधिकारियों द्वारा कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का निरीक्षण किया गया, जिसमें पर्याप्त ओबीएचएस स्टाफ, लिनेन की गुणवत्ता और पेंट्री कार की स्वच्छता की जाँच की गई। यात्रियों को बायो-टॉयलेट, फ्लशिंग सिस्टम और कचरा न फैलाने जैसी आदतों के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान भी आयोजित किए गए।

स्टेशनों के ब्लॉक सेक्शन और आस-पास के क्षेत्रों में पटरियों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया। पटरियों के किनारे बने नाले भी सफाई अभियान में शामिल किए गए। साथ ही, कचरे और अवांछित झाड़ियों को हटाया गया।

इन निरंतर प्रयासों से मण्डल ने स्वच्छ भारत मिशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है और अपने नेटवर्क में यात्रियों एवं समुदायों को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा

- महंगाई भत्ते में जुलाई-2025 से केंद्र की तर्ज पर बढ़ोतरी करने का मुख्यमंत्री का कर्मचारी हितैषी दृष्टिकोण
- छठे तथा सातवें वेतन आयोग का लाभ प्राप्त कर रहे राज्य सेवा, पंचायत सेवा एवं अन्य कर्मचारियों सहित कुल 4.69 लाख कर्मचारियों और 4.82 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा लाभ
- महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का 3 महीने का बकाया एक किस्त में दिया जाएगा

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के व्यापक हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय करते हुए छठे और सातवें वेतन आयोग का लाभ प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2025 से केंद्र की तर्ज पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ देने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री के इस कर्मयोगी हितैषी निर्णय के अंतर्गत सातवें वेतन आयोग का लाभ प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा किया गया है। वहीं, छठे वेतन आयोग का लाभ प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।

इस महंगाई भत्ते की 3 महीने की अर्थात 1 जुलाई, 2025 से 30 सितंबर, 2025 तक की बकाया राशि यानी एरियर का भुगतान एक किस्त में किया जाएगा।

महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी का लाभ राज्य सरकार और पंचायत सेवा के कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों सहित कुल 4.69 लाख कर्मयोगियों और लगभग 4.82 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों यानी पेंशनरों को मिलेगा। इतना ही नहीं, राज्य सरकार इस एरियर के तहत कर्मचारियों को कुल 483.24 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। वहीं, वेतन, भत्ते और पेंशन के लिए वार्षिक अतिरिक्त 1932.92 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। मुख्यमंत्री ने इस कर्मचारी हितैषी निर्णय के कार्यान्वयन के लिए वित्त विभाग को आवश्यक आदेश जारी करने के निर्देश भी दिए हैं।

श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात की सफल सर्वग्राही विकास यात्रा के 24 वर्षों की सफलता का जश्न मनाने के लिए 'विकास सप्ताह' का प्रारंभ

- मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों, मुख्य सचिव और वरिष्ठ सचिवों एवं पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए मन, वचन और कर्म से तत्पर रहने के साथ ही देश के प्रति समर्पण भाव की सामूहिक 'भारत विकास प्रतिज्ञा' ली
- विधानसभा पोडियम में सामूहिक प्रतिज्ञा पठन
- नागरिक भारत विकास प्रतिज्ञा पोर्टल- https://pledge.mygov.in/bharat-vikas/ पर ऑनलाइन तरीके से प्रतिज्ञा लेकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं

गांधीनग : श्री नरेन्द्र मोदी ने 7 अक्टूबर, 2001 को गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर राज्य की विकास यात्रा को एक नया आयाम दिया था।

उनके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में गुजरात की 2001 से 2025 तक की 24 वर्षों की सर्वग्राही वैश्विक विकास यात्रा की सफलता गाथा में जनभागीदारी के साथ 7 से 15 अक्टूबर तक चलने वाले 'विकास सप्ताह' के जश्न की शुरुआत 'भारत विकास प्रतिज्ञा' से हुई।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों, मुख्य सचिव और वरिष्ठ सचिवों एवं पदाधिकारियों ने विधानसभा पोडियम में आयोजित सामूहिक प्रतिज्ञा पठन कार्यक्रम में शामिल होकर 'भारत विकास प्रतिज्ञा' ली।

देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण का जो संकल्प किया है, उसे साकार करने में अपना संपूर्ण योगदान देने के लिए सभी लोगों ने मन, वचन और कर्म से तत्पर रहने के साथ ही देश के प्रति समर्पण भाव की सामूहिक भारत विकास प्रतिज्ञा की।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल सहित मंत्रियों और मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी एवं वरिष्ठ सचिवों द्वारा ली गई 'भारत विकास प्रतिज्ञा' इस प्रकार है:-

मैं भारत के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में प्रतिज्ञा करता हूँ कि...

- मैं अपने जीवन के हर पल में देश के लिए समर्पित रहूँगा।
- मैं स्वयं के बारे में सोचने से पहले दूसरों के कल्याण के बारे में विचार करूंगा। मैं देश के सभी संसाधनों का न्यायसंगत एवं सतत उपयोग सुनिश्चित करूंगा। मैं देश के सर्वांगीण और समावेशी विकास के लिए निःस्वार्थ भाव से निरंतर प्रयासरत रहूंगा।
- मैं अपने देश की समृद्ध परंपरा और विरासत पर गर्व अनुभव करूंगा तथा उसे संरक्षित रखने का निरंतर प्रयास करूंगा।
- मैं अपने देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहूंगा और उनके संरक्षण में योगदान दूंगा।
- मैं जाति, धर्म या वर्ण के सभी बंधनों से मुक्त होकर, बंधुता और एकता की भावना के साथ अपने देश को सर्वोच्च प्राथमिकता दूंगा। मैं 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के आदर्श को साकार करने हेतु भारत की एकता और अखंडता की रक्षा में निरंतर प्रयासरत रहूंगा।
- मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए अपने मन, वचन और कर्म से निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा।
- "हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी" के आदर्श को अपनाकर, मैं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना सर्वोत्तम योगदान देने का प्रयास करूंगा।
- 'राष्ट्र प्रथम' को अपने जीवन का मूलमंत्र बनाकर, मैं अपने देश के विकास और कल्याण हेतु तन, मन और धन से सतत कार्य करता रहूंगा।

विकास सप्ताह के जश्न के अंतर्गत भारत विकास प्रतिज्ञा ऑनलाइन तरीके से भी ली जा सके, इस उद्देश्य से पोर्टल- https://pledge.mygov.in/bharat-vikas/ शुरू किया गया है। राज्य के नागरिक इसका लाभ उठा सकते हैं और प्रतिज्ञा लेकर उसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्र प्रथम के भाव को उजागर करने वाली एक अद्वितीय प्रस्तुति 'मेरा देश पहले' गुजरात में पहली बार 10 अक्टूबर को गिफ्ट सिटी में आयोजित होगी

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आकार ले रहे नए भारत के रूपांतरण की एक अनोखी कहानी 'मेरा देश पहले' का गुजरात में पहला शो शुक्रवार, 10 अक्टूबर, 2025 को गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में आयोजित होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित किया है। उनके पूरे जीवन की अनेक घटनाएं और अवसर देशवासियों में देश प्रेम, समर्पण और राष्ट्र प्रथम का भाव जागृत करने के लिए प्रेरणादायी बनी हैं। 'मेरा देश पहले' श्री नरेन्द्र मोदी के एक अद्वितीय सफर को मेगा शो के माध्यम से जीवंत करता है।

उल्लेखनीय है कि देश के अन्य राज्यों में 'मेरा देश पहले' के सफल और प्रशंसनीय मंचन के बाद, गुजरात में पहली बार गिफ्ट सिटी परिसर में यह शो निःशुल्क प्रवेश के साथ आयोजित होने जा रहा है।

शुक्रवार, 10 अक्टूबर को शाम 6.00 बजे गिफ्ट सिटी में आयोजित होने वाले इस शो को देखने के लिए केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए ही निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की गई है। इसके लिए www.giftgujarat.in पर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।

सुप्रसिद्ध कलाकार श्री मनोज मुंतशिर की प्रस्तुति 'मेरा देश पहले' का मंचन देखने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और मंत्रियों के साथ-साथ कई सामाजिक अग्रणियों को भी आमंत्रण दिया गया है।

रेलवे में विकास की क्रांति — 24,000 करोड़ की चार मेगा परियोजनाओं से चमकेगा 18 जिलों का भविष्य

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में चार महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनकी कुल अनुमानित लागत 24,634 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद 18 जिलों के लगभग 86 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार के अनुसार, ये सभी परियोजनाएं अगले छह वर्षों में यानी वित्तीय वर्ष 2030–31 तक पूरी की जाएंगी। इनके अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों — महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात — में कुल 894 किलोमीटर नई मल्टी-ट्रैक लाइनों का निर्माण होगा। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क की क्षमता और कनेक्टिविटी दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ये परियोजनाएं 3,600 से अधिक गांवों को जोड़ेंगीं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, व्यापार और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। जिन चार मेगा परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, उनमें सबसे बड़ी परियोजना महाराष्ट्र के वर्धा से भुसावल के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण है, जिसकी लंबाई 314 किलोमीटर होगी। इसके अलावा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से गुजरने वाली गोंदिया–डोंगरगढ़ सेक्शन में 84 किलोमीटर लंबी चौथी लाइन बनेगी। वहीं गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच वडोदरा–रतलाम सेक्शन में 259 किलोमीटर की तीसरी और चौथी लाइन तैयार की जाएगी। चौथी बड़ी परियोजना मध्य प्रदेश के इटारसी–भोपाल–बीना रूट की

है, जहां 237 किलोमीटर की चौथी लाइन बनाई जाएगी।

रेल मंत्रालय का कहना है कि इन परियोजनाओं से रेल यातायात की क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में इन मार्गों पर यात्री और मालगाड़ियां दोनों अत्यधिक दबाव में चलती हैं। नई लाइनों के निर्माण से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी, विलंब में कमी आएगी और माल ढुलाई की लागत घटेगी। ये सभी परियोजनाएं प्रधानमंत्री मोदी के "आत्मनिर्भर भारत" और "न्यू इंडिया" के विजन का हिस्सा हैं। इन्हें "पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान" के तहत लागू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करना और देश के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को अधिक कुशल बनाना है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा बल्कि स्थानीय स्तर पर हजारों नए रोजगार भी सृजित होंगे। निर्माण कार्यों में बड़ी संख्या में स्थानीय श्रमिकों, इंजीनियरों और छोटे उद्योगों को जोड़ा जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधि और सामाजिक विकास दोनों को बल मिलेगा। इन परियोजनाओं का लाभ सिर्फ परिवहन या व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पर्यटन और पर्यावरण को भी नई दिशा मिलेगी।

प्रस्तावित रेल लाइनों से सांची स्तूप, भीमबेटका रॉक शेल्टर, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, हजारा फॉल्स और नावागांव नेशनल पार्क जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की पहुंच और भी आसान हो जाएगी।

इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देशी-विदेशी पर्यटकों की आवाजाही में वृद्धि होगी।

पर्यावरणीय दृष्टि से भी ये परियोजनाएं लाभकारी सिद्ध होंगी। रेलवे के अनुसार, नई लाइनों के बनने से प्रतिवर्ष लगभग 78 मिलियन टन अतिरिक्त माल का परिवहन रेलमार्ग से किया जा सकेगा, जिससे सड़कों पर ट्रकों का दबाव घटेगा। इससे लगभग 28 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी और 139 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। यह पर्यावरणीय प्रभाव लगभग 6 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर होगा।

इन रेल परियोजनाओं के पूरा होने के बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन और परिवहन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। कोयला, सीमेंट, स्टील, अनाज और कंटेनर जैसी वस्तुओं के परिवहन में तेजी आने से न केवल औद्योगिक विकास को बल मिलेगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सशक्त होगी।

कुल मिलाकर, भारतीय रेलवे की ये चार मेगा परियोजनाएं न सिर्फ ट्रेनों की गति बढ़ाने की दिशा में एक तकनीकी सुधार हैं, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाली ठोस आर्थिक आधारशिला भी हैं। इनसे देश की कनेक्टिविटी, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन — सभी क्षेत्रों में नया संतुलन और नई ऊर्जा आने की उम्मीद है।

राज्य सरकार की नूतन पहल : ‘वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंसेज’

जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम तथा नीदरलैंड जैसे देश तथा जेट्रो, इंडो-कनाडा बिजनेस चैम्बर, यूएसआईएसपीएफ, विश्व बैंक एवं रशियन फेडरेशन का व्यापार प्रतिनिधित्व जैसे संस्थान होंगे सहभागी

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ‘वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंसेज’ की प्रथम श्रृंखला का 9 अक्टूबर को मेहसाणा से कराएंगे शुभारंभ :
-उद्योग मंत्री श्री बलवंतसिंह राजपूत

राज्य के प्रत्येक प्रदेश की औद्योगिक-आर्थिक क्षमता तथा निवेश की सज्जता का प्लेटफॉर्म बनेंगी ‘वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंसेज’
-उद्योग आयुक्त श्री पी. स्वरूप

▸▸ राजकोट में 8-9 जनवरी को, सूरत में 9-10 अप्रैल को और वडोदरा में 10-11 जून, 2026 को आयोजित होगी रीजनल कॉन्फ्रेंस

▸▸ प्रत्येक क्षेत्रीय संमेलन दो दिन आयोजित होंगे; जिनमें विभिन्न परिसंवाद, प्रदर्शनियाँ, क्षेत्रीय पुरस्कार, एमओयू, बीटुबी-बीटुजी बैठकें, खरीद-बिक्री बैठकों का प्लेटफॉर्म, विक्रेता मार्गदर्शन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुई वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट (वीजीजीसी) की भारी सफलता के चलते मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात ने एक और नूतन पहल करते हुए ‘वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंसेज’ (वीजीआरसी) आयोजित करने का निश्चय किया है। इन ‘वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंसेज’ की प्रथम श्रृंखला का मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल मेहसाणा से 9 अक्टूबर को शुभारंभ कराएंगे।

उद्योग मंत्री श्री बलवंतसिंह राजपूत ने मंगलवार को गांधीनगर में संवाददाता संमेलन में वीजीआरसी के विषय में यह जानकारी दी। इस संवाददाता संमेलन में उद्योग एवं खान विभाग की प्रधान सचिव श्री ममता वर्मा, इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ब्यूरो (इंडेक्स्ट-बी) के प्रबंध निदेशक श्री के. सी. संपत, सूचना निदेशक श्री के. एल. बचाणी उपस्थित थे।

उद्योग मंत्री की उपस्थिति में उद्योग आयुक्त श्री पी. स्वरूप ने वीजीआरसी के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि ‘वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंसेज’ राज्य के प्रत्येक प्रदेश की औद्योगिक-आर्थिक क्षमता एवं निवेश सज्जता का एक अनूठा प्लेटफॉर्म बनेंगी। इतना ही नहीं; यह कार्यक्रम वाइब्रेंट समिट से ग्लोबल इंडस्ट्रियल मैप पर स्थापित हुई गुजरात की छवि को ‘वोकल फॉर लोकल’ के माध्यम से अधिक उजागर करने में परिणामकारी बनेगा।

उन्होंने जोड़ा कि गुजरात में आयोजित हुई गत वाइब्रेंट समिट की सफलता के फलस्वरूप मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में हर जिले, तहसील एवं गुजरात के सुदूरवर्ती मानव को वाइब्रेंट गुजरात से जोड़ा जा सके; इसके लिए ‘वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंसेज’ का आयोजन किया गया है। इसमें उत्तर गुजरात अंचल की मेहसाणा में 9-10 अक्टूबर 2025 को, कच्छ एवं सौराष्ट्र अंचल की राजकोट में 8-9 जनवरी 2026 को, दक्षिण गुजरात अंचल की सूरत में 9-10 अप्रैल 2026 को तथा मध्य गुजरात अंचल की वडोदरा में 10-11 जून 2026 को ‘वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस’ आयोजित होगी।

श्री स्वरूप ने कहा कि गुजरात सरकार ने अब तक 10 ‘वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट’ का सफलतापूर्वक आयोजन किया है और ‘वाइब्रेंट गुजरात के 20 वर्ष सफलता के समिट’ विषय पर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया है। वाइब्रेंट गुजरात के सफल मॉडल को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए राज्य सरकार अब वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय संमेलनों का आयोजन कर रही है। ये संमेलन वीजीजीसी की सफलता के मानदंडों के अनुसार ही आयोजित होंगे। क्षेत्रीय स्तर पर उपस्थित औद्योगिक घरानों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने तथा वे स्थानीय औद्योगिक विकास में उत्प्रेरक बनें; इस तरह विकसित भारत@2047 तथा विकसित गुजरात@2047 के व्यापक विजन के साथ सुगठित विकास के लिए ये संमेलन एक महत्वपूर्ण माध्यमरूपी बनेंगे।

इतना ही नहीं; अंचल के हर जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम तथा उसके बाद क्षेत्रीय संमेलन आयोजित होगा। क्षेत्रीय संमेलन के लगभग एक-दो माह पहले जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होंगे; जिसमें भिन्न-भिन्न हिस्सेदारों के साथ विचार-विमर्श, जिले की विशिष्ट चुनौतियों की पहचान, श्रेष्ठ बातों का वृत्तचित्रीकरण तथा आगामी क्षेत्रीय संमेलन की आवश्यकताएँ निश्चित की जाएंगी। उन्होंने जोड़ा कि उत्तर गुजरात के वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय संमेलन के लिए अरवल्ली, बनासकाँठा, पाटण तथा साबरकाँठा में जिला स्तरीय कार्यक्रम पूर्ण हो गए हैं।

उद्योग आयुक्त ने कहा कि क्षेत्रीय संमेलन दो दिन आयोजित होंगे। ये संमेलन जिला स्तरीय आवश्यकताओं के संदर्भ में निवेश सुविधा, वैचारिक आदान-प्रदान तथा नेटवर्किंग के लिए एक प्रभावशाली माध्यम के रूप में सेवा देंगे। इन संमेलनों के जरिये उद्योगपतियों, उद्यमियों, सरकारी संस्थाओं, विदेशी व्यापार घरानों, व्यापार एवं उद्योग संगठनों, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों सहित विभिन्न हिस्सेदारों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इसके अतिरिक्त; हर क्षेत्रीय संमेलन में उद्घाटन व समापन सत्र, क्षेत्र विशिष्ट अथवा जिला विशिष्ट परिसंवाद, व्यापार प्रदर्शनी, क्षेत्रीय पुरस्कार, एमओयू पर हस्ताक्षर, बीटुबी तथा बीटुजी बैठकें, खरीद-बिक्री बैठकों का प्लेटफॉर्म, विक्रेता मार्गदर्शन कार्यक्रम, अग्रगण्य पर्यटन स्थलों तथा स्थानीय औद्योगिक क्लस्टरों की पर्यटन यात्राओं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने जोड़ा कि ये क्षेत्रीय संमेलन केवल क्षेत्रीय उपलब्धियाँ दर्शाने तथा नए आयामों की घोषणा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में ही नहीं, अपितु क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाकर, श्रेष्ठता को प्रोत्साहन देकर एवं रणनीतिक निवेशों को सरल बनाकर गुजरात की विकास गाथा को आगे बढ़ाने की राज्य सरकार की मंशा हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 28 अगस्त 2025 को अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय संमेलनरूपी पहल का आधिकारिक प्रारंभ कराया था। इसके अलावा; नई दिल्ली में उद्योगपतियों, मिशन प्रमुखों, राजनयिकों तथा भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इंटरेक्शन मीट भी आयोजित की थी। वाइब्रेंट गुजरात अंतर्गत मेहसाणा में आयोजित होने वाली वीजीआरसी में क्रॉस सेक्टरल फोकस कौशल विकास, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, पर्यटन तथा संस्कृति को शामिल किया गया है।

वीजीआरसी (उत्तर गुजरात)

9 अक्टूबर 2025 गुरुवार
- ▸▸ उद्घाटन समारोह
- ▸▸ 21 सेमिनार
- ▸▸ 2 राउंडटेबल कॉन्फ्रेंस
- ▸▸ 3 पैनल चर्चाएँ
- ▸▸ वडनगर में सांस्कृतिक कार्यक्रम

10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार
- ▸▸ रीजनल एमएसएमई कॉन्क्लेव
- ▸▸ 11 सेमिनार
- ▸▸ 10 पैनल चर्चाएँ
- ▸▸ वेंडर डेवलपमेंट कार्यक्रम
- ▸▸ समापन सत्र

इन दोनों दिन उद्यमी मेला, रिवर्स बायर-सेलर मीट तथा बीटुबी/बीटुजी मीटिंग का आयोजन किया जाएगा।

▸▸ क्षेत्रीय प्रदर्शनी 9 से 13 अक्टूबर 2025 के दौरान एग्जीबिनशन हॉल में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक प्रदर्शनी आयोजित होगी, जो 11 से 13 अक्टूबर 2025 तक लोगों के लिए खुली रहेगीष 18,000 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र में आयोजित होने वाली इस प्रदर्शनी में एमएसएमई, कुटीर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1000 वर्ग मीटर का पैवेलियन बनाया जाएगा।

मुख्य विशेषताओं में रिवर्स बायर-सेलर मीट, पार्टनर कंट्री पैवेलियन, बीटुजी व बीटुबी जोन, स्टार्टअप स्टॉल तथा उद्यमी मेला शामिल हैं। अन्य सुविधाओं में वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, रीजनल फूड फेस्ट, फूड कोर्ट, ओडीओपी तथा जीआई टैग डिसप्ले, सांस्कृतिक प्रदर्शनी, प्रोडक्ट लॉन्च, फूड प्रदर्शनी, दैनिक लकी ड्रॉ, हेल्पडेस्क, कंट्रोल रूम तथा पॉप-अप स्टेज शामिल हैं।

▸▸ रिवर्स बायर-सेलर मीट में कुल 40 देशों से 38 अंतरराष्ट्रीय खरीदार सहभागी होंगे, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रत्येक खरीदार के लिए अवसर उपलब्ध होंगे।

कृषि : गेहूँ, बाजरा, आलू, टमाटर, सोयाबीन, चीकू आदि।

मसाले : जीरा, सौंफ, इसबगोल, धनिया, रायडा आदि।

डेयरी उत्पाद : दूध, चीज, दूध पाउडर, मिठाइयाँ, मक्खन आदि।

ऑटोमोबाइल : स्पेयरपार्ट्स तथा घटक

फूड प्रोसेसिंग : पीनट बटर, पोटैटो चिप्स और अन्य।

9 व 10 अक्टूबर 2025 के दौरान पर्यटन एवं उद्योग यात्राएँ

सुबह 8 बजे से पूरे दिन की पर्यटन यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसमें अनंत अनादि वडनगर में बौद्ध मठ, संग्रहालयों, मंदिरों तथा सांस्कृतिक प्रदर्शनियों, अंबाजी में आध्यात्मिक यात्रा (अंबाजी मंदिर व गब्बर पर्वत), गुजरात में बुद्ध क विरासतों (तारंगा गुफाएँ व पुरातत्वीय स्थलों), प्रकाश से गहराई तक : मंदिर एवं वाव (रानी की वाव, पटोळा संग्रहालय, मोढेरा सूर्य मंदिर) और लाइन ऑफ ड्यूटी : नडाबेट में एक दिन (भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित आकर्षणों, संग्रहालयों तथा रीट्रीट परेड) शामिल हैं।

सुबह 9 बजे से आधे दिन की यात्राएँ शुरू होंगी। इनमें सांस्कृतिक व विरासत के अनुभव दर्शाए जाएंगे; जैसे कि रानी की वाव तथा पटोळा म्यूजियम, मोढेरा सूर्य मंदिर, लाइट एंड साउंड शो, सिद्धपुर, सोलवोक (धार्मिक विधियाँ व विरासत स्थल) और पृथ्वी की प्रतिध्वनि (बालासिनोर डायनासोर पार्क तथा म्यूजियम)।

औद्योगिक यात्राओं में मोढेरा सूर्य मंदिर (आधा दिन), चारणका स्थित गुजरात का प्रथम सोलर पार्क तथा राधनेसडा स्थित 700 मेगावाट यूएमएसपीपी शामिल हैं। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले उद्योगकार, स्टार्टअप तथा विद्यार्थी, जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हों, उन लोगों को उद्योग संबंधी प्रैक्टिकल ज्ञान देने के उद्देश्य से औद्योगिक इकाइयों की स्थल मुलाकात का आयोजन किया गया है। इस स्थल मुलाकात के दौरान डेलीगेट्स को सम्बद्ध उद्योग गृह में उत्पादन प्रक्रिया, कच्चे माल की उपलब्धता, बिक्री के अवसरों के बारे में जानकारी दी जाएगी। वाइब्रेंट कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को मारुति सुजुकी, होंडा मोटर्स, बनास डेयरी, दूध सागर डेयरी, साबर डेयरी, फणीधर फूड पार्क जैसे महत्वपूर्ण उद्योग गृहों व इकाइयों की मुलाकात करवा कर उन उद्योगों से जुड़ी प्रैक्टिकल जानकारी देने का आयोजन किया गया है।

यहाँ उल्लेखनीय है कि 6 अक्टूबर तक कुल 13,246 पंजीकरण हुए हैं। इनमें 216 अंतरराष्ट्रीय सहित कुल 11,732 व्यक्तिगत तथा 35 अंतरराष्ट्रीय सहित 1514 कंपनियाँ सहभागी होने वाली हैं। इसके अलावा; जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम तथा नीदरलैंड (कृषि परिसंवाद) जैसे देशों ने सहभागी होने की पुष्टि की है और जेट्रो, इंडो-कनाडा बिजनेस चैम्बर (आईसीबीसी), यूएसआईएसपीएफ, विश्व बैंक, रशियन फेडरेशन का व्यापार प्रतिनिधिमंडल जैसे संस्थान भी सहभागी होंगे।

इस कॉन्फ्रेंस में राजनियकों-राजदूतों/उच्चायुक्तों ने भी उपस्थित रहने की सहमति दी है। इनमें भारत में जापान (सहभागी देश) के राजदूत श्री केइची ओनो, भारत में वियतनाम (सहभागी देश) के विशेष एवं पूर्णाधिकारी राजदूत श्री गुयेन थान हाई, भारत में न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त श्री पैट्रिक जॉन राटा, भारत में रवांडा गणराज्य की उच्चायुक्त श्री जैक्लीन मुकनगिरा, भारत में गुयाना के उच्चायुक्त श्री धरमकुमार सीराज, भारत में यूक्रेन दूतावास के राजदूत डॉ. अलेक्जेंडर पोलिशचुक शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त; केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, इसरो के अध्यक्ष डॉ. वी. नारायणन, विश्व बैंक के दक्षिण एशिया के उपाध्यक्ष श्री जोहान्स जूट, टोरेंट समूह के उपाध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री जिनल मेहता, अदाणी सीमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, एपीएस कार्यपालक निदेशक तथा अध्यक्ष श्री करण अदाणी, अरविंद लि. के उपाध्यक्ष श्री कुलीन लालभाई, सेवी के प्रबंध निदेशक श्री जक्षय शाह, अमूल के प्रबंध निदेशक श्री मनीष किरी व श्री गणपत पटेल, श्री शंकर चौधरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी, श्रीमती नेहा मेहता, श्री हितुभाई कनोडिया, श्री असितकुमार मोदी और डॉ. करसनभाई पटेल जैसे अग्रणी भी उपस्थित रहेंगे।

अन्य तीन रीजनल कॉन्फ्रेंसेज के फोकस क्षेत्र

कच्छ तथा सौराष्ट्र अंचल की कॉन्फ्रेंस 8-9 जनवरी 2026 को सौराष्ट्र विश्वविद्यालय-राजकोट में आयोजित होगी, जिसमें सिरामिक्स, इंजीनियरिंग, पोर्ट्स तथा लॉजिस्टिक्स, मत्स्योद्योग, पेट्रोकेमिकल्स, कृषि एवं खाद्य प्रक्रिया, खनिज, ओफशोर पवन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

दक्षिण गुजरात अंचल की कॉन्फ्रेंस 9-10 अप्रैल 2026 को सूरत अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं संमेलन केन्द्र, एसजीसीसीआई, सूरत में आयोजित होगी। इसमें केमिकल्स तथा पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल व एपेरल, जेम्स एंड ज्वैलरी, कृषि एवं खाद्य प्रक्रिया जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

मध्य गुजरात अंचल की कॉन्फ्रेंस 10-11 जून 2026 के दौरान दीनदयाल उपाध्याय नगर गृह, वडोदरा में आयोजित होगी। इसमें सेमीकंडक्टर तथा ईएसडीएम, आईटी एंड आईटीईएस, बायोटेक/बायोफार्मा, एयरोस्पेस तथा रक्षा, फिनटेक, केमिकल्स तथा पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल व एपेरल, ऑटो तथा ऑटो कम्पोनेंट्स, शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

गुजरात सरकार का कड़ा कदम — दो दवा कंपनियों का उत्पादन तत्काल प्रभाव से बंद, बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता

गुजरात। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अहम और सख्त कदम उठाया है। राज्य में निर्मित और वितरित दवाओं की “मानक गुणवत्ता” (एनएसक्यू) का पालन न करने पर गुजरात सरकार ने तुरंत दो दवा कंपनियों — सुरेंद्रनगर की ‘शेप फार्मा प्राइवेट लिमिटेड’ और अहमदाबाद की ‘रेडनेक्स फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड’ — को सभी प्रकार की दवाओं का उत्पादन बंद करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कथित तौर पर “विषाक्त” कफ सिरप ‘कोल्ड्रिफ’ पीने से बच्चों की मौतों की पृष्ठभूमि में उठाई गई है।

राज्य स्वास्थ्य मंत्री और प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने बताया कि हाल ही में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बच्चों के लिए बनाए गए कुछ कफ सिरप को एनएसक्यू घोषित किया गया, जिनमें से कुछ सिरप गुजरात की इन दो कंपनियों द्वारा निर्मित थे। इस गंभीर खुलासे के बाद राज्य खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशास और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की संयुक्त टीम ने तीन और पांच अक्टूबर को दोनों कंपनियों के विनिर्माण केंद्रों का गहन निरीक्षण किया।

जांच के दौरान कई कमियां पाई गईं। निरीक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि दोनों कंपनियों के परिसरों में एनएसक्यू दवा की कोई मात्रा उपलब्ध नहीं थी। इसके आधार पर अधिकारियों ने दोनों कंपनियों को तत्काल प्रभाव से अपने सभी उत्पादन संचालन बंद करने का आदेश दिया। इसके साथ ही राज्यभर के दवा विक्रेताओं को निर्देश दिया गया कि वे इन एनएसक्यू सिरप को न बेचें और तुरंत वापस करें।

इसके अतिरिक्त, दोनों कंपनियों द्वारा निर्मित अन्य कफ सिरप के चौदह नमूने एकत्र किए गए हैं और सरकारी प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। गुजरात में कुल 624 लाइसेंस प्राप्त तरल दवा निर्माता कंपनियां हैं, जो राज्य और बाहर अधिकृत वितरकों के माध्यम से अपने उत्पादों की आपूर्ति करती हैं। सरकारी प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में गुजरात एफडीसीए ने राज्य में निर्मित और वितरित दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए सभी सहायक आयुक्तों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि सभी ओरल लिक्विड और कफ सिरप निर्माण कंपनियों का गहन निरीक्षण किया जाए, जिसमें पानी की गुणवत्ता, कच्चे माल के स्रोत, उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की पूरी जांच की जाएगी। यह कदम बच्चों और आम जनता की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे सख्त उपाय सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में किसी भी तरह की घातक या हानिकारक दवा बाजार में नहीं पहुँच सके और राज्य में दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य रूप से हो।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: भाजपा का नया नारा और नीतीश मोदी जोड़ी की ताकत

बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और जैसे-जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक माहौल और गरम होता जा रहा है। इस बार भाजपा ने चुनावी रणभूमि में एक नया नारा देकर अपने गठबंधन की एकजुटता और नेतृत्व को लेकर स्पष्ट संदेश दिया है: “25 से 30, हमारे दो भाई- नरेंद्र और नीतीश।” इस नारे के माध्यम से भाजपा ने यह संकेत दे दिया है कि 2025 से 2030 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे और एनडीए उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा। यह ऐलान विपक्ष के उस दावे का भी जवाब माना जा रहा है, जिसमें बार-बार कहा जा रहा था कि भाजपा चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा सकती है।

भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने पहले भी कई बार स्पष्ट किया था कि एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार होंगे। अब इस नारे के जरिए यह वादा और अधिक मजबूत हुआ है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर भी चुनावी प्रचार की गति बढ़ा दी है। भाजपा के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से लगातार संदेश जारी किए जा रहे हैं, जैसे, “बिहार में जारी रहेगी विकास की तेज रफ्तार, 14 नवंबर को फिर एक बार एनडीए सरकार।” वहीं एक अन्य संदेश में लिखा गया, “जनता का विश्वास, फिर से NDA सरकार! बस 38 दिन का है इंतज़ार, थमेगी नहीं विकास की रफ्तार।” इन संदेशों और नारों के जरिए भाजपा जनता को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ही बिहार में विकास और स्थिरता की गारंटी है।

केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी चुनाव की घोषणा के बाद सीधे जनता से अपील की। उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि बिहार में विकास और सुशासन को आगे बढ़ाने का अवसर है। नड्डा ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार जनकल्याण और सुशासन का पर्याय बन चुकी है। यह चुनाव बिहार को विकास के रास्ते पर बनाए रखने, घुसपैठ और जंगलराज से बचाने का चुनाव है।” भाजपा और जदयू के बीच तालमेल इस बार पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने नीतीश कुमार को “बड़ा भाई” मानते हुए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, जबकि जदयू को केवल 43 सीटें मिली थीं। इसके बावजूद भाजपा ने मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार का समर्थन जारी रखा। इस बार का नया नारा भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें भाजपा यह संदेश देना चाहती है कि एनडीए में स्थिरता है और विकास का एजेंडा अगले पांच साल तक बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा।

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह नारा विपक्ष के उस नैरेटिव को तोड़ने का प्रयास है जिसमें कहा जा रहा था कि भाजपा नीतीश को किनारे करने की योजना बना रही है। इस नारे के साथ भाजपा यह भी संदेश देना चाहती है कि 2025 से 2030 तक बिहार में वही नेतृत्व रहेगा और जनता का विश्वास टूटने नहीं पाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि यह मोदी-नीतीश जोड़ी जनता को कितना भरोसा दिला पाती है। विपक्ष इस बार आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ मिलकर पहले से अधिक सक्रिय दिखाई दे रहा है। बिहार की राजनीति इस बार विकास, स्थिरता और गठबंधन के एजेंडे के इर्द-गिर्द घूमती दिखाई दे रही है, और भाजपा का यह नया नारा चुनावी रणभूमि में उसकी रणनीति को और स्पष्ट करता दिख रहा है।

यह नारा और सोशल मीडिया प्रचार स्पष्ट संकेत है कि भाजपा नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, ताकि जनता में यह विश्वास बना रहे कि बिहार में अगली सरकार स्थिर, सक्षम और विकासोन्मुख होगी।

सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ — यूपी ग्रामीण बैंक के असिस्टेंट मैनेजर के नेतृत्व में फर्जीवाड़े की धांधली, लखनऊ से 9 सदस्य गिरफ्तार, नौकरी 5 लाख में बिकती थी

लखनऊ। राजधानी की पुलिस ने एक बड़े और संगठित सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश करते हुए नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें गैंग का सरगना बताया जा रहा असिस्टेंट मैनेजर भी शामिल है। यह शिकंजा तब कसा गया जब 5 अक्टूबर को बिजनौर के एक परीक्षा केंद्र पर आईबीपीएस क्लर्क परीक्षा 2025 के दौरान संदिग्ध गतिविधि ने अधिकारियों का ध्यान खींचा। घटना की चेन तब से जुड़ी कई पड़तालों और पूछताछों से खुलती चली गई, जिससे सामने आया कि कैसे संगठित गिरोह परीक्षा फॉर्म, फोटो-हेरफेर और तकनीकी चालाकी के सहारे उम्मीदवारों की जगह फर्जी परीक्षार्थियों को बैठाकर लाखों रुपये वसूल कर रहा था और सरकारी नौकरियों की सप्लाई जैसी धांधली चला रहा था।

यह सारा खेल बेहद योजनाबद्ध था। पहले एक संदिग्ध की सूचना पर जब पुलिस ने जांच की तो बोधगया (बिहार) निवासी एक व्यक्ति हिरासत में आया, जिसने स्वीकार किया कि वह किसी और की जगह परीक्षा दे रहा था। पूछताछ से सवालों के तार जुड़े और पुलिस ने गति पकड़ते हुए बिजनौर अण्डरपास से कुल नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरोह का मस्तक आनन्द कुमार बताया जा रहा है, जो यूपी ग्रामीण बैंक खबूपुरा संभल में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात था। गिरोह में पोस्ट-ग्रेजुएट, बैंक कर्मचारी, अन्य बैंक क्लर्क और कुछ छात्र भी शामिल थे — यानी कुछ आरोपी वर्तमान में सरकारी नौकरी कर रहे थे तो कुछ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे।

जांच में कई भेद स्पष्ट हुए। गैंग की रणनीति यह थी कि असली उम्मीदवार के फॉर्म पर फर्जी व्यक्ति का नाम/फोटो सेट कर दिया जाता; फोटो मिलान के जोखिम को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता। आरोपियों ने फेस-मिक्सिंग ऐप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर असली और फर्जी चेहरे को लगभग 70 प्रतिशत मिलाया जाता था, ताकि केंद्र पर प्रवेश और पहचान के समय शंका न उठे। इसके अलावा आर्थिक लेन-देन भी स्पष्ट रूप से श्रेणीकृत था — प्रारम्भिक चरण की फीस और मुख्य परीक्षा में बैठाने के लिए अलग-अलग राशि ली जाती और नौकरी लग जाने के बाद शेष वसूला जाता। गिरफ्तार आरोपियों की पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि कुल मिलाकर प्रति उम्मीदवार करीब पांच लाख 20 हजार रुपये की लेन-देन की योजना थी — प्रारम्भिक में 20 हजार, मुख्य परीक्षा में 1 लाख और नियुक्ति के बाद 2 लाख रुपये तथा अन्य मध्यवर्ती किस्तें। यह गिरोह केवल परीक्षा-प्रवेश तक सीमित नहीं था, बल्कि नौकरी दिलाने के नाम पर दीर्घकालिक धांधली चला रहा था। आनन्द कुमार जैसे बैंक के अंदर तक जुड़े पदस्थ व्यक्ति की उपस्थिति से यह रैकेट और भी संगठित और विश्वसनीय दिखता था, जिससे ग्राहक — प्रतियोगी अभ्यर्थी — आसानी से धोखे में आ जाते।

पुलिस ने बताया कि रोहित नामक एक संदिग्ध असली अभ्यर्थियों को गैंग के पास लाता था; वहां अभ्यर्थियों के डेटा और फोटो का उपयोग कर फर्जी उम्मीदवार तैयार किए जाते थे। यह पूरा नेटवर्क कई राज्यों से जुड़े लोगों का था, जैसे पटना, गया, जहानाबाद, लखीसराय, नालन्दा और उत्तराखंड के चम्पावत तक के नाम कार्यालयीक रूप से जुड़ते मिले।

पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद जब ठोस सबूत इकट्ठा किए तो पाया कि न सिर्फ उम्मीदवार केंद्रों पर बैठते, बल्कि परीक्षा के बाद भी इस व्यवस्था के सहारे नौकरी पाने के कई मामले संपन्न हुए हैं या इसके प्रयास चल रहे थे। इसलिए अब अपराध की गंभीरता को देखते हुए जांच को विस्तारित कर दिया गया है और कई और एंगल पर छानबीन जारी है — जैसे कि फॉर्म भरे जाने के स्रोत, पैसों का लेन-देन किस रास्ते से होता था, कितने अभ्यर्थियों को यह सुविधा दी गई, और क्या कुछ सरकारी प्रक्रियाओं में मिलीभगत थी।

यह मामला सिर्फ एक परीक्षा-घोटाले का मामला नहीं है; यह उस भरोसे पर चोट है जो समाज और सरकार शिक्षा एवं भर्ती प्रक्रियाओं पर करते हैं। जब शैक्षणिक और भर्ती परीक्षा जैसी संस्थागत प्रक्रियाओं में टेक्नोलॉजी के जरिए हेराफेरी हो सकती है और बैंक जैसे संवेदनशील संस्थान के कर्मचारी इसका संचालन कर सकते हैं, तो सिस्टम की कमियों पर गंभीर चिंतन अनिवार्य हो जाता है। ऐसे मामलों से न केवल इमानदार उम्मीदवारों के अवसर छिनते हैं, बल्कि संस्थागत विश्वसनीयता को भी भारी धक्का पहुँचता है।

इसीलिए पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरणों की फोरेंसिक जांच की जा रही है ताकि चेहरे-मिश्रण ऐप्स, लेन-देन के रिकॉर्ड और अन्य सबूत जुटाए जा सकें। साथ ही केन्द्र और राज्य परीक्षा प्राधिकरणों को भी झटके में सतर्क किया गया है, ताकि अगली परीक्षाओं में प्रवेश-प्रक्रिया, आईडी सत्यापन और बायोमेट्रिक मिलान जैसी व्यवस्था और सख्त की जाए। अधिकारी यह भी कह रहे हैं कि तकनीक का उपयोग ही ठगी को पकड़ने में सहायक होगा — यानी एआई और डिजिटल फोरेंसिक से भ्रष्टाचार का मुकाबला करने की रणनीति अपनाई जाएगी। गिरफ्तार किए गए नौ आरोपियों में बैंक के शीर्षक वाले कर्मचारी और परीक्षा-तैयारी कर रहे कुछ युवक भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ अब विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि अभी और पूछताछ बाकी है और गिरोह के और सदस्यों की पहचान के लिए छानबीन चल रही है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत जल्द ही आरोपियों को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा और मामले की न्यायिक जांच के लिए सबूत कांग्रेसित किए जाएंगे।

झारखंड में महिला मुंशी की तैनाती विवाद में फंसी, पुलिस मुख्यालय में जारी हैं लेटर बम

रांची। झारखंड में महिला पुलिसकर्मियों की थानों में मुंशी के रूप में तैनाती को लेकर पुलिस महकमे में गहरी खींचतान शुरू हो गई है। झारखंड सशस्त्र पुलिस (जैप), इंडियन रिजर्व बटालियन (IRB) और स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन (SIRB) की 212 महिला पुलिसकर्मियों को थानों में मुंशी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाना था, लेकिन यह योजना फिलहाल विवाद का रूप ले चुकी है। इस मामले में झारखंड पुलिस मुख्यालय में लगातार “लेटर बम” फूट रहे हैं और उच्चाधिकारियों के बीच तीखी बहस चल रही है। एडीजी प्रिया दुबे ने डीजीपी कार्यालय पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दो बार पत्राचार किया है। उन्होंने कहा कि अब तक के इतिहास में किसी पूर्व डीजीपी ने ऐसा आदेश नहीं दिया जैसा अब जारी किया जा रहा है। उनके अनुसार जिलों के एसपी स्तर से होने वाली पदस्थापना का कार्य अब डीजीपी कार्यालय कर रहा है, जो कि पूर्व निर्देशों और प्रशासनिक प्रथाओं के खिलाफ है। चार अक्टूबर को एडीजी ने अपने नियंत्रण वाले जैप, IRB और SIRB की सभी बटालियनों को आदेश पत्र जारी किया कि वे डीजीपी कार्यालय के पदस्थापन आदेशों का पालन न करें और संबंधित महिला पुलिसकर्मियों को विरमित न करें।

इससे पहले भी एडीजी प्रिया दुबे ने डीआईजी कार्मिक को पत्र लिखा था, जिसमें महिला आरक्षियों की थानों में तैनाती पर सवाल उठाए गए थे। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को जारी आदेश को रद्द किया जाना चाहिए, अन्यथा इस प्रतिनियुक्ति आदेश का पालन संभव नहीं होगा। एडीजी ने आईआरबी वाहिनियों में 15% से अधिक बल को बिना हथियार ड्यूटी में प्रतिनियुक्त न करने वाले पूर्व निर्देश का हवाला देते हुए बताया कि वर्तमान आदेश के कारण कई वाहिनियों में यह सीमा उल्लंघन हो रहा है। उनके अनुसार आईआरबी-1 में 40%, आईआरबी-8 में 37%, आईआरबी-10 में 34% और जैप-7 में 40% महिला आरक्षियों को थानों में प्रतिनियुक्त किया गया है। महिला थानों में मुंशी कार्य के लिए कुल 212 महिला आरक्षियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जबकि इससे पहले भी 89 महिला आरक्षियों को इसी तरह तैनात किया गया था। एडीजी प्रिया दुबे का तर्क है कि ये वाहिनियां विशेष रूप से उग्रवादियों के खिलाफ अभियान और विधि व्यवस्था के लिए बनाई गई थीं और इन जवानों को आर्म्स ड्यूटी के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। यदि इन्हें थानों में मुंशी कार्य के लिए तैनात किया गया, तो उनका प्रशिक्षण व्यर्थ जाएगा और सुरक्षा बलों की क्षमता प्रभावित होगी। इस विवाद ने झारखंड पुलिस महकमे के भीतर तनाव को बढ़ा दिया है और उच्चाधिकारियों के बीच पदस्थापना और नियमों के पालन को लेकर संघर्ष को उजागर कर दिया है। अब यह देखना बाकी है कि महिला पुलिसकर्मियों की थानों में तैनाती और उग्रवाद नियंत्रण कार्यों के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाएगा।

भावनगर टर्मिनस से चलने वाली भावनगर – शहीद कप्तान तुषार महाजन जन्मभूमि एक्सप्रेस अगले आदेश तक रद्द

यात्रियों की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि परिचालन कारणों के चलते पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल से चलने वाली भावनगर टर्मिनस – शहीद कप्तान तुषार महाजन जन्मभूमि एक्सप्रेस अस्थायी रूप से निरस्त (Cancelled) रहेगी।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि संबंधित ट्रेनों के निरस्तीकरण का विस्तृत विवरण इस प्रकार हैः

1. ट्रेन संख्या 19107 – भावनगर टर्मिनस – शहीद कप्तान तुषार महाजन जन्मभूमि एक्सप्रेस को पूर्व में दिनांक 12.10.2025 तक रद्द किया गया था, जिसे अब अगले आदेश तक पूर्णतः निरस्त (Fully Cancelled) कर दिया गया है।
2. ट्रेन संख्या 19108 – शहीद कप्तान तुषार महाजन जन्मभूमि – भावनगर टर्मिनस एक्सप्रेस को पूर्व में दिनांक 13.10.2025 तक रद्द किया गया था, जिसे अब अगले आदेश तक पूर्णतः निरस्त (Fully Cancelled) कर दिया गया है।

यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा की योजना बनाते समय उक्त जानकारी का संज्ञान लें। ट्रेन के ठहराव, संरचना एवं समय-सारणी संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया भारतीय रेल की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन करें।

पश्चिम रेलवे द्वारा लिफ्टों, एस्केलेटरों और अर्थिंग पिट्स के लिए स्मार्ट डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम ‘सुगम रेल’ लॉन्च

पश्चिम रेलवे ने डिजिटल गवर्नेंस तथा यात्री सुरक्षा के क्षेत्र में एक और उपलब्धि अर्जित की है। सुगम रेल भारतीय रेल पर अपनी तरह का पहला सॉफ्टवेयर आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसे लिफ्टों, एस्केलेटरों और अर्थिंग पिट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए डिजाइन किया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह एप्लिकेशन पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता के नेतृत्व में विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य मुख्य सुरक्षा और रखरखाव प्रणालियों में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना है। इससे पहले लिफ्टों, एस्केलेटरों और अर्थिंग अवसंरचना का पर्यवेक्षण कई डिपो में बनाए गए मैनुअल रजिस्टरों पर निर्भर था, जिसके कारण खराबी का पता लगाने में देरी, फ्रेगमेंटेड रिपोर्टिंग और सीमित जवाबदेही होती थी। सुगम रेल के कार्यान्वयन के साथ पश्चिम रेलवे में 470 से अधिक लिफ्ट/एस्केलेटर और लगभग 21,500 अर्थिंग पिट अब एक

एकीकृत डिजिटल डैशबोर्ड के अंतर्गत आ गए हैं, जो मंडल और मुख्यालय स्तर पर अधिकारियों के लिए सुलभ है। यह प्रणाली उपकरणों की स्थिति की चौबीसों घंटे निगरानी सुनिश्चित करती है, बार-बार होने वाली खराबी या अतिदेय निरीक्षणों को स्वचालित रूप से चिह्नित करती है और उच्च अनुपालन के साथ समय पर हस्तक्षेप को सक्षम बनाती है। यह परिसंपत्ति-वार और कारण-वार विस्तृत विफलता विश्लेषण प्रदान करती है, जबकि विफलताओं के बीच औसत समय (एमटीबीएफ) और रखरखाव अनुपालन दर जैसे प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) का उपयोग परिसंपत्ति विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए किया जाता है।

अपने परिचालन लाभों के अलावा, यह पहल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है। लिफ्ट और एस्केलेटर के प्रदर्शन की डिजिटल ट्रैकिंग, ब्रेकडाउन पर तेज़ी से ध्यान देने में मदद करती है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन यात्रियों और बच्चों के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं को लाभ होता है। साथ ही, अर्थिंग प्रतिरोध की संरचित निगरानी विद्युत खतरों को रोकने में मदद करती है और स्टेशनों और रेलवे प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करती है। भौतिक रजिस्टरों को डिजिटल, एनालिटिक्स-समर्थित तंत्र से बदलकर, पश्चिम रेलवे ने रेलवे अवसंरचना प्रबंधन में एक नया मानदंड स्थापित किया है। सुगम रेल के चालू होने के साथ पश्चिम रेलवे ने सुरक्षित, स्मार्ट और जवाबदेह रेल संचालन के लिए बुद्धिमान डिजिटल समाधानों को अपनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की है। यह प्लेटफ़ॉर्म सार्वजनिक सेवा वितरण में उभरती माँगों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए नवपरिर्तन के एक मॉडल के रूप में खड़ा है।